Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 70
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
बुधवार, 18 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

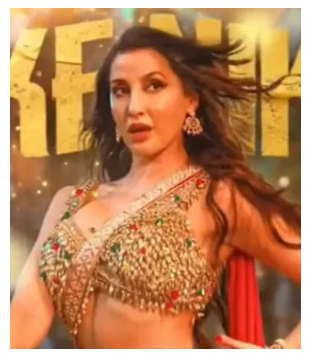

3 नशे के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' नीति...

4 अगले दस साल में बीमारियां खत्म कर...

7 स्क्वाश के ओलंपिक का हिस्सा बनने के बाद...

संक्षिप्त न्यूज

एंटनी राजू की याचिका खारिज; चुनाव लड़ने पर संशय बरकरार, सबूतों से छेड़छाड़ का लगा था आरोप

नई दिल्ली। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व परिवहन मंत्री एंटनी राजू की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। यह याचिका आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई थी। न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन ने राजू की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल उनकी सजा बरकरार रहेगी। मामले में विस्तृत आदेश का इंतजार है।

क्या है पूरा मामला?

राजू, जो जनधिपत्य केरल कांग्रेस के नेता हैं और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) का हिस्सा रहे हैं, को नेदुमंगड की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने 1990 के एक ड्रग्स मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई थी। उस समय वह एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के वकील के रूप में पेश हुए थे।

सजा के बाद विधायक पद से हुए थे अयोग्य घोषित

सजा के बाद केरल विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित कर दिया था। राजू तिरुवनंतपुरम सेंट्रल सीट से विधायक थे।

राजू ने क्या दी दलील?

अपनी याचिका में राजू ने दलील दी थी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत उनकी अयोग्यता स्वतः और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिससे उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जब तक दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगती, तब तक उनकी स्थिति बहाल नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी दावा किया कि निचली अदालत का फैसला तथ्यों और कानून के खिलाफ है और साक्ष्यों के मूल्यांकन में गंभीर त्रुटियां हुई हैं।

एलपीजी आपूर्ति संकट पर सरकार का डबल एक्शन विवेकपूर्ण उपयोग की अपील, कालाबाजारियों पर ताबड़तोड़ छापे

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की संभावित कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, केंद्र ने सोमवार को ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग का आग्रह किया और पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस (पीएनजी) के बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देने का संकेत दिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्राकृतिक गैस के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत सरकार प्रयास कर रही है और यदि सभी वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ता पीएनजी (पेट्रोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) पर निर्भर हो जाएं तो यह लाभकारी होगा।

शर्मा ने बताया कि प्रवर्तन कार्रवाई के संबंध में, अब तक पिछले कुछ दिनों में लगभग बारह हजार छापे मारे गए हैं। लगभग पंद्रह हजार सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कल दिल्ली में लगभग छह सौ सिलेंडर जब्त किए गए। इसी तरह, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगभग चार सौ पचास निरीक्षण और छापे मारे गए हैं। दस लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जम्मू और कश्मीर में पांच सौ चौंसठ छापे मारे गए हैं, एफआईआर दर्ज की गई हैं और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। केरल में लगभग एक हजार छापे और निरीक्षण किए गए हैं और घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगभग बारह सौ छापे मारे गए हैं और लगभग अठारह सौ सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, हमारी तेल विपणन कंपनियों की निरीक्षण टीमों को भी सक्रिय किया गया है और लगभग ढाई हजार खुदरा दुकानों और एलपीजी वितरकों पर अचानक निरीक्षण किए गए हैं।

भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में हमारे सभी नाविक और जहाज सुरक्षित हैं... पिछले 24 घंटों में, खाड़ी क्षेत्र में अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद 161 भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस भारत लाया गया है। यह कार्य हमारे दूतावासों और मिशनों के समन्वय से किया गया। दूसरा एलपीजी वाहक, नंदा देवी, आज सुबह लगभग 2:30 बजे कांडला पहुंचा, और अब दोनों एलपीजी वाहकों, शिवालिक और नंदा देवी से माल उतारा जा रहा है। कई जहाजों से माल उतारा जा रहा है। नंदा देवी से माल उतारने की प्रक्रिया जहाज-से-जहाज, यानी मुख्य जहाज से सहायक जहाज तक है। यह प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही और माल संचालन को सुचारू बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आज सुबह एक समाचार रिपोर्ट आई थी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर लगभग 450 कंटेनर सड़क पर पड़े हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट निराधार है। कंटेनर सीएफएस (कंटेनर फ्रेट स्टेशन), गोदाम और कारखाने परिसर में हैं, जो जेएनपीए की नीति के अनुसार हैं।

भाजपा-एनडीए से गठबंधन की अटकलों पर विराम

तमिलनाडु में अकेले चुनाव लड़ेंगे विजय

चेन्नई। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) ने भाजपा-एनडीए के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि वह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इस घोषणा के बाद राज्य में डीएमके, एआईएडीएमके और एनडीए के बीच संभावित चार-कोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई है।

तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके) ने उन खबरों को बेबुनियाद और पूरी तरह झूठा बताया, जिनमें कहा गया था कि पार्टी 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके और भाजपा के साथ गठबंधन वार्ता कर रही है। अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली पार्टी की ओर से यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आया, जिनमें दावा किया गया था कि टीवीके को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने के लिए उपमुख्यमंत्री पद के साथ लगभग 50 से 70 सीटें देने की पेशकश की गई है।

सोमवार रात विजय ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए दोहराया कि उनकी पार्टी, तमिलगा वेत्री कज़गम (टीवीके), आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि टीवीके और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच बातचीत अंतिम चरण में है।

विजय ने यह घोषणा पट्टिनापक्कम में टीवीके के पदाधिकारियों की बैठक में की। उन्होंने कहा कि पार्टी ने किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं की है और वह अपने पहले चुनावी मुकाबले में स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेगी। विजय ने बैठक में कहा, 'हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे।

'लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने से टूट रहा सीएपीएफ के जवानों का हौसला', संसदीय समिति की चेतावनी

नई दिल्ली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के पर्यवेक्षी स्तरों पर लंबे समय से जारी ठहराव के कारण जवानों के मनोबल और करियर की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह चिंता संसद की एक स्थायी समिति ने व्यक्त की है। समिति ने इन बलों के रैंकों की 'व्यापक कैडर समीक्षा' की सिफारिश की है ताकि रिक्तियों की स्थिति, पदोन्नति के अवसरों और समय-सीमा का आकलन किया जा सके।

समिति की मुख्य सिफारिशें

गृह मामलों पर स्थायी समिति ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पदोन्नति कोटे का युक्तियुक्तिकरण, विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकों का समय पर आयोजन और कैडर संरचना की समीक्षा जैसे उचित उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष और समयबद्ध करियर प्रगति ढांचा सुनिश्चित करना है। समिति, जिसकी अध्यक्षता राधा मोहन दास अग्रवाल ने की, ने यह भी सिफारिश की कि कई सीएपीएफ के अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच करियर की प्रगति में समानता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

कैडर समीक्षा और वर्तमान स्थिति

रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सीएपीएफ और असम राइफल्स में कैडर समीक्षा के उपाय किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त पदों का सृजन, रैंक संरचनाओं का युक्तियुक्तिकरण और पदोन्नति में ठहराव को दूर करने के कदम शामिल हैं।

विधानसभा चुनाव की तैयारीः निर्वाचन आयोग ने तैनात किए 1111 पर्यवेक्षक, मतदान को पारदर्शी बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली। देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव के चलते तेज होती राजनीति के बीच अब चुनाव आयोग ने भी बड़ा एलान किया है। आयोग ने बताया कि अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के लिए 1,111 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने हैं। इसके अलावा कई राज्यों में अप्रैल में विधानसभा उपचुनाव भी आयोजित होंगे।

क्यों तैनात किए गए हैं पर्यवेक्षक?

बता दें कि पर्यवेक्षक अपनी तैनाती के बाद अपने संपर्क विवरण सार्वजनिक करेंगे और रोजाना एक निश्चित समय तय करेंगे, जब उम्मीदवार, राजनीतिक दल या जनता के किसी भी सदस्य चुनाव से जुड़े शिकायत या सुझाव लेकर उनसे मिल सके। इस कदम का मकसद है कि चुनाव साफ-सुथरे, पारदर्शी और सभी के लिए निष्पक्ष तरीके से संपन्न हों।

चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव

बता दें कि बीते 15 मार्च रविवार को चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। इनमें असम, केरल, पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं।असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे।

जनगणना 2027 पर बड़ा ऐलानः

नित्यानंद राय बोले- दो चरणों में होगी जनगणना, ऑनलाइन का भी मिलेगा विकल्प

नई दिल्ली। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 17 मार्च को बताया कि जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में घरों की सूची बनाना और आवास संबंधी आंकड़े एकत्र करना शामिल होगा, जिसके बाद जनसंख्या गणना की जाएगी। राय ने बताया कि पहले चरण के प्रश्न अधिसूचित किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे चरण के प्रश्न जनसंख्या गणना शुरू होने से पहले अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर दिए जाएंगे। पिछले जनगणना अभ्यासों की तरह, दूसरे चरण में विकलांगता संबंधी आंकड़े भी शामिल किए जाने की उम्मीद है।

प्रश्नावली को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, इस अभ्यास की तैयारियों में विस्तृत निर्देश पुस्तिकाएँ और प्रशिक्षण उपकरण शामिल होंगे। इन्हें हितधारकों के परामर्श से विकसित किया जाएगा, जिसके बाद जनगणना कर्मचारियों,

हैं, के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। गणनाकर्ता निर्धारित ब्लॉकों में घर-घर जाकर डेटा एकत्र करेंगे। स्व-गणना की एक वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध होगी, जिससे 'परिवार का कोई भी सदस्य' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विवरण जमा कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के प्रश्नों को अंतिम रूप देने और अधिसूचित किए जाने के बाद, संबंधित हितधारकों के परामर्श से निर्देश पुस्तिका और प्रशिक्षण उपकरण किट तैयार किए जाते हैं तथा गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों सहित जनगणना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। वहीं, सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 93,000 से अधिक पद रिक्त हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों में रिक्तियों के आंकड़े पेश किए, जिसके अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सबसे अधिक 27,400 पद रिक्त हैं। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) है, जिसमें 28,342 पद खाली हैं।

उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 14,531 रिक्तियां हैं, जबकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 12,333 और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 6,784 रिक्त पद हैं। असम राइफल्स में 3,749 रिक्तियां हैं। रिक्त पदों के कारण कानून प्रवर्तन, आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर जताई जा रही चिंताओं के संदर्भ में राय ने कहा कि बल अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, "बल उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अत्यंत पेशेवर तरीके से सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

महिला आरक्षण पर खरगे ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, कहा- पीएम मोदी तुरंत बुलाएं सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू से कहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम के "क्रियान्वयन के तौर-तरीकों और रूपरेखा" पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। रीजीजू द्वारा उन्हें लिखे गए एक पत्र का जवाब देते हुए, खरगे ने कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम', सितंबर 2023 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोमवार रात रीजीजू को लिखे पत्र में कहा, "30 महीने बाद, सरकार संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और रूपरेखा पर विचार-विमर्श करने के लिए मेरे और मेरी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत करने का अवसर तलाश रही है। कुछ दिन पहले आपने मुझसे इस मामले पर बात की थी।"

खरगे ने कहा, "मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसा कि राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने भी कहा है कि कांग्रेस का विचार है कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जहां सभी विपक्षी दलों के साथ इस तरह की रूपरेखा पर चर्चा की जा सके।" कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ऐसी सर्वदलीय बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाएगी। यह संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपराओं को ध्यान में रखते हुए होगी।" सरकार संभवतः लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की संभावना तलाश रही है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बीते सप्ताह 'पीटीआई-भाषा' से कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए औपचारिक प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते अब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन संसद द्वारा 2023 में पारित कानून में संशोधन की संभावना तलाशने की योजना बनाई जा रही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान में संशोधन करके लाया गया था, लेकिन यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा। यदि परिसीमन प्रक्रिया से पहले ही कानून को लागू करने का प्रस्ताव वास्तव में आता है, तो संविधान में एक और संशोधन की आवश्यकता होगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक (106वां संविधान संशोधन) सितंबर 2023 में पारित किया गया, जो अब कानून बन चुका है। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक-तिहाई) सीट आरक्षित करने का प्रावधान है।

पूर्व पीएम ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, संसद में अराजकता पर जताई चिंता; कांग्रेस नेता दिया यह जवाब

नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एचडी देवगौड़ा ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद के भीतर हो रहे हंगामे और सांसदों द्वारा संसद परिसर में किए जा रहे प्रदर्शनों पर गहरी चिंता जताई। अपने पत्र में देवगौड़ा ने कहा कि वह संसद के अंदर और उसके परिसर में बिना सोचे-समझे फैलाई गई अराजकता से काफी परेशान हैं। देवेगौड़ा ने इस अराजकता के लिए मुख्य रूप से विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया।

'संसद में नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन की घटनाएं बढ़ीं'

पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने पत्र में लिखा, 'मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने संसद और उसके परिसर में व्यवधान उत्पन्न किए हैं। उन्होंने संसद परिसर में किए जा रहे धरनों और घेराव को अभूतपूर्व करार दिया। हाल के समय में संसद में नारेबाजी, तख्तियां दिखाने और एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने की घटनाएं बढ़ी हैं। गंभीरता की कमी का यह रवैया संसद और संसदीय लोकतंत्र

पर आघात करता है।'

'संसद में इतनी अराजकता कभी नहीं देखी'

देवेगौड़ा ने लिखा, संसदीय लोकतंत्र की उनकी समझ देश के संस्थापक नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, बी.आर. आंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आजाद से मिली सीख पर आधारित है। देवगौड़ा ने कहा, 'अपने लंबे राजनीतिक अनुभव में मैंने संसद को इस तरह की अराजकता और हल्केपन के साथ पहले कभी नहीं देखा। अपने पूरे करियर में, अत्यधिक उकसावे के बावजूद, मैंने कभी भी विरोध के लिए सदन के वेल में प्रवेश नहीं किया। यही परंपरा हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमें सिखाई थी।'

देवेगौड़ा ने सोनिया गांधी की तारीफ की

सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए देवेगौड़ा ने कहा कि विपक्ष में लंबे समय तक रहते हुए उन्होंने गरिमा और परिपक्वता के साथ आचरण किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी से आग्रह किया कि वह अपने पार्टी नेताओं और अन्य विपक्षी दलों से बात करें और उन्हें समझाएं। उन्होंने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि आप आवश्यक कदम उठाएंगी। विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन यह विरोध ऐसे तरीके से होना चाहिए, जो पिछले 75 वर्षों में मिलकर बनाए गए लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर न करे।' देवगौड़ा ने चेतावनी दी कि संसद में नकारात्मक माहौल लोकतंत्र की बुनियाद को नुकसान पहुंचा सकते हैं और स्थायी कटुता पैदा कर सकता है।

सोनिया बोलीं- आपकी चिंताओं पर ध्यान है, उगादी की दी शुभकामनाएं

वहीं सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उनकी चिंताओं को ध्यान से पढ़ लिया है और नोट कर लिया है। साथ ही उन्होंने उगादी और गुड़ी पड़वा पर उन्हें शुभकामनाएं भी दीं। दरअसल, देवगौड़ा ने पत्र लिखकर संसद में हो रहे हंगामे और विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस के सांसद, ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, जिससे संसद की गरिमा प्रभावित हो रही है। इस पर सोनिया गांधी ने संक्षिप्त जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने उनकी बातों को गंभीरता से लिया है।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन का सवाल

छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान पर संजय राउत चुप क्यों?

दिव्यांश

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन ने मंगलवार को तीखा हमला करते हुए कहा कि धर्मांध तत्वों का समर्थन करने और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले संजय राउत ने जितेंद्र आव्हाड द्वारा विधानसभा में वंदनीय छत्रपति शिवाजी महाराज के कथित अपमान पर एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण की आड़ में हिंदू अस्मिता को ठेस पहुंचाने की राजनीति राउत, उबाठा गुट और कांग्रेस द्वारा बार-बार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का हवाला देते हुए आव्हाड द्वारा दिया गया बयान अत्यंत आपत्तिजनक है, लेकिन राउत और उनके सहयोगी इस पर मौन साधे हुए हैं, जो निंदनीय है।

श्री बन ने आगे कहा कि आव्हाड की यह पुरानी आदत रही है कि वे हिंदू योद्धाओं का अपमान करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा किया था कि 'औरंगजेब था इसलिए शिवाजी महाराज थे', जो इतिहास को विकृत करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ और आव्हाड द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए

बार-बार इतिहास को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है, लेकिन राउत और उनका गुट इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।

एलपीजी आपूर्ति को लेकर स्थिति नियंत्रण में

श्री बन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति के बावजूद देश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को तीन जहाज और मंगलवार को एक और जहाज पहुंच चुका है, जिससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ स्थानों पर गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में गैस बुकिंग पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। मुंबई में आपूर्ति सामान्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी बाधा आई है, जिसे शीघ्र ठीक किया जा रहा है।

युद्ध के बावजूद नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

उन्होंने कहा कि ईरान और इज़राइल के बीच तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और कई देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बहुत अधिक हो चुकी हैं, जबकि भारत में स्थिरता बनी हुई है, जो मजबूत नेतृत्व का परिणाम है।

महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी निशाना

श्री बन ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ सबसे अधिक अन्याय महाविकास आघाड़ी सरकार और कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वैधानिक मंडलों को निष्क्रिय कर दिया था।

उन्होंने यह भी कहा कि मविआ सरकार के कार्यकाल में भाजपा के 105 विधायकों को कोई फंड नहीं दिया गया और 12 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से निलंबित किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि उस समय निष्पक्षता की बात करने वाले नेता आज क्यों चुप हैं।

महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे (प्रभारी) द्वारा रतलाम-चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण

रतलाम, 17 मार्च। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक (प्रभारी) प्रदीप कुमार द्वारा 17 मार्च 2026 को रतलाम मंडल के प्रवास के दौरान रतलाम-चित्तौड़गढ़ रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य रेल संरक्षा एवं परिचालन व्यवस्थाओं का समग्र मूल्यांकन करना था।

चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर मीडिया से चर्चा के दौरान महाप्रबंधक श्री कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सिग्नलिंग प्रणाली, ट्रैक की स्थिति, पुलों की संरचना तथा विद्युतीकरण कार्यों का गहन परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि रेल संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी दृष्टिकोण से नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं।

महाप्रबंधक ने आगे बताया कि नीमच-रतलाम रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का भी जायजा लिया गया। यह कार्य लगभग पूर्णता की ओर है। मंदसौर-दलौदा तथा रतलाम-धौसवास खंड के लगभग 18 किलोमीटर हिस्से में कार्य शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। इस परियोजना के पूर्ण होते ही चित्तौड़गढ़-रतलाम रेलखंड पूर्ण रूप से दोहरीकृत हो जाएगा। इससे मालगाड़ियों एवं यात्री गाड़ियों के संचालन में सुगमता आएगी, क्रॉसिंग संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी तथा यात्रियों का यात्रा समय कम होगा।

निरीक्षण के दौरान मंदसौर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास एवं निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। यहां नई स्टेशन

बिल्डिंग, फुट ओवर ब्रिज सहित विभिन्न यात्री सुविधाओं का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रगति पर है।

महाप्रबंधक कुमार ने यह भी जानकारी दी कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना अंतिम चरण में है और इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए प्राथमिकता के साथ कार्य किया जा रहा है।

इस निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं सुरक्षित रेल संचालन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

सोलापुर जिले के चिंचोली काटी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण मामले की जांच के बाद कंपनियों को नोटिस- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। सोलापुर जिले के मोहोळ तालुका के चिंचोली काटी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण संबंधी शिकायत मिलने पर संबंधित कंपनियों का निरीक्षण किया गया। जांच में कुछ त्रुटियां पाए जाने के बाद कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है और उनकी बैंक गारंटी भी जब्त की गई है। यदि आगे की विस्तृत जांच में किसी प्रकार का नियम उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने विधान सभा में दी।

विधान सभा में सदस्य राजू खरे ने सोलापुर जिले के मोहोळ विधानसभा क्षेत्र के चिंचोली काटी औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पानी छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुद्दा उठाया था। इस पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने उत्तर दिया। इस चर्चा में सदस्य अर्जुन खोतकर ने भी भाग लिया।

मंत्री मुंडे ने बताया कि चिंचोली काटी औद्योगिक क्षेत्र में 1.5 एमएलडी क्षमता का सामूहिक अपशिष्ट जल शोधन प्रकल्प स्थापित किया गया है, जिसे 36 उद्योगों ने मिलकर स्थापित किया है। इस प्रकल्प पर ऑनलाइन निगरानी प्रणाली कार्यरत है और प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसके संचालन की निगरानी कर रहा है। संबंधित उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट जल टैंकर या पाइप के माध्यम से इस प्रकल्प तक लाया जाता है और वहां उसका शोधन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी 2026 को कृषि विभाग से मांगी गई रिपोर्ट में

खेती को किसी प्रकार की हानि होने की बात सामने नहीं आई है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में भी दूषित पानी के कारण मनुष्यों या पशुओं को किसी प्रकार की हानि का उल्लेख नहीं किया गया है।

हालांकि निरीक्षण के दौरान कुछ अनियमितताएं पाई गईं। मंत्री मुंडे ने बताया कि खतरनाक कचरे के प्रबंधन में त्रुटि, सीसीटीवी की अनुपस्थिति, जल प्रबंधन की कमी, शोधन प्रकल्प का सही तरीके से काम न करना तथा भंडारण क्षमता से अधिक भंडारण जैसी कमियों के कारण संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनकी बैंक गारंटी जब्त की गई है।

मंत्री मुंडे ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर उद्योगों को तुरंत बंद करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इन उद्योगों से रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। फिर भी सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का सम्मान करते हुए वह स्वयं सोलापुर जाकर चिंचोली काटी औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करेंगी, संबंधित विधायकों के साथ स्थल निरीक्षण करेंगी और आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

पश्चिम रेलवे एवं एसबीआई द्वारा दिवंगत रेल कर्मचारी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान सौंपा गया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल के एक वरिष्ठ मोटरमैन, जिनका ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में दुखद निधन हो गया था, उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की बीमा राशि प्रदान की गई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मुंबई सेंट्रल मंडल में इस प्रकार का पहला बीमा भुगतान है, जो सितंबर 2025 में भारतीय रेल और भारतीय स्टेट बैंक के बीच उन्नत रेलवे सैलरी पैकेज (एइ) योजना के अंतर्गत हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (श्दळ) के तहत संभव हो पाया।

मुंबई सेंट्रल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज सिंह तथा भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई मेट्रो सर्कल की मुख्य महाप्रबंधक

श्रीमती मंजू शर्मा ने 16 मार्च, 2026 को मुंबई सेंट्रल मंडल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को एक करोड़ रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर रेलवे एवं एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुंबई सेंट्रल मंडल के कार्मिक विभाग ने सभी देयकों के समयबद्ध भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एक्स-ग्रेशिया तथा अन्य पात्र मुआवजे शामिल हैं। यह बीमा राशि, रेलवे की नीति के अनुसार पहले से प्रदान किए गए अन्य सेटलमेंट लाभों के अतिरिक्त है।

आरएसपी योजना के अंतर्गत, एसबीआई में वेतन खाते रखने वाले रेल कर्मचारियों को व्यापक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ बीमा सुरक्षा भी प्राप्त होती है, जिसमें बिना किसी प्रीमियम या चिकित्सीय जांच के एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है। दिवंगत वरिष्ठ मोटरमैन ने इस योजना का लाभ लिया था, जिससे उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।

यह पहल भारतीय रेल द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण तथा उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अहमदाबाद रेल मंडल में 'कवच 4.0' का तेजी से विस्तारः सुरक्षित सफर की ओर बढ़ते कदम

अहमदाबाद-पालनपुर, सामाख्याली और गांधीधाम रेल मार्गों पर कवच स्थापना कार्य प्रगति पर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। यह उच्च प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है, जिसके लिए उच्चतम स्तर (एसआईएल-4) का सुरक्षा प्रमाणन आवश्यक होता है। यह प्रणाली लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन संचालन में सहायता करती है। यदि लोको पायलट निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, तो यह प्रणाली स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन को नियंत्रित करती है तथा खराब मौसम में भी ट्रेनों के सुरक्षित संचालन में मदद करती है।

कवच प्रणाली का उद्देश्य ट्रेनों की टक्कर को रोकना, संकेत उल्लंघन से बचाव करना तथा सुरक्षित और नियंत्रित रेल संचालन सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत रेल पथ पर विशेष पहचान टैग लगाए जाते हैं। लोकोमोटिव में लगे रीडर के माध्यम से ट्रेन की सटीक स्थिति, संकेत की अवस्था और गति सीमा की जानकारी प्राप्त होती है।

अहमदाबाद मंडल में कवच प्रणाली का क्रियान्वयन

भारतीय रेल द्वारा विकसित इस उन्नत स्वदेशी प्रणाली का क्रियान्वयन अहमदाबाद मंडल में तेज गति से किया

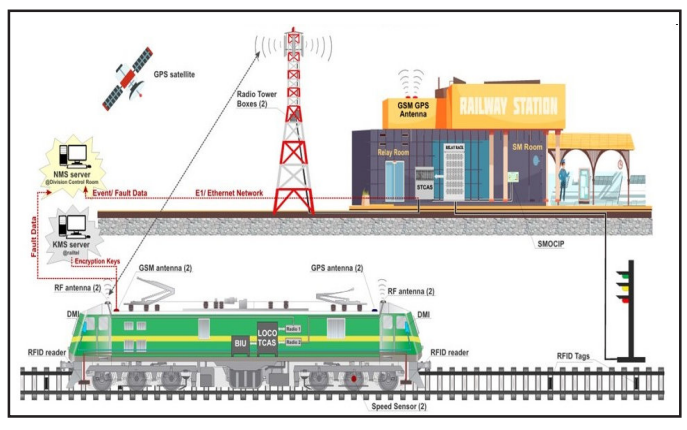

जा रहा है। यह पहल रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, उत्तरदायी और नियंत्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

1. वटवा लोको शेड में प्रगति

वटवा लोको शेड में कुल 180 इंजनों पर कवच प्रणाली स्थापित करने की योजना है।

अब तक 72 इंजनों पर स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

शेष इंजनों पर कार्य प्रगति पर है।

इसके लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की समर्पित टीम तैनात की गई है।

2. साबरमती लोको शेड में प्रगति

साबरमती लोको शेड में 34 इंजनों पर कवच स्थापित किया जाना है।

इनमें से 6 इंजनों पर परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है।

शेष इंजनों पर स्थापना कार्य जारी है।

3. रेल पथ खंडों पर कवच स्थापना की स्थिति अहमदाबाद-पालनपुर तथा अहमदाबाद-सामाख्याली खंड

कुल लंबाईः 402 मार्ग किलोमीटर

अनुमानित लागतः 410.10 करोड़ रुपये

कार्य प्रगति पर है।

पालनपुर-सामाख्याली-गांधीधाम खंड

कुल लंबाईः 300 मार्ग किलोमीटर

अनुमानित लागतः 182.81 करोड़ रुपये

कार्य प्रगति पर है।

अहमदाबाद-गेरतपुर खंड

कुल लंबाईः 13.42 किलोमीटर

इस खंड में कवच प्रणाली की स्थापना पूर्ण हो चुकी है।

परीक्षण और सफल परिणाम

अहमदाबाद मंडल के सभी खंडों में पहचान टैग लगाए जा चुके हैं तथा कवच युक्त इंजनों का परीक्षण पूरा किया गया है।

गांधीनगर कैपिटल और कलोल के बीच लगभग 20 किलोमीटर खंड में सफल परीक्षण किया गया।

परीक्षण के दौरान दो ट्रेनों को एक ही रेल पथ के एक ही खंड में चलाया गया। जैसे ही दोनों ट्रेनें लगभग 10 किलोमीटर की दूरी के भीतर आईं, पीछे चल रही ट्रेन में स्वतः ब्रेक लग गया।

यदि कोई ट्रेन उसी खंड में प्रवेश करती है तो प्रणाली स्वतः ब्रेक लगाकर चेतावनी ध्वनि भी देती है।

जब दोनों इंजनों को आमने-सामने लाने का प्रयास किया गया, तब भी दोनों में स्वतः ब्रेक लग गए और संभावित टक्कर टल गई।

राष्ट्रीय स्तर पर कवच का विस्तार

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा जैसे व्यस्त मार्गों पर 1,452 मार्ग किलोमीटर पर कवच 4.0 का संचालन प्रारंभ हो चुका है।

रेल संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 8,570 किलोमीटर प्रकाश तंतु केबल, 1,100 टावर और 6,776 मार्ग किलोमीटर ट्रैकसाइड उपकरण स्थापित किए गए हैं।

साथ ही 767 स्टेशन डेटा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

भारतीय रेल के गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन डायगोनल और उच्च घनत्व नेटवर्क सहित कुल 24,427 मार्ग किलोमीटर रेल पथ पर कवच प्रणाली लागू करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

निष्कर्ष- भारतीय रेल की यह पहल न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से ट्रेन संचालन को अधिक उत्तरदायी और नियंत्रित बनाती है। अहमदाबाद मंडल में कवच प्रणाली का विस्तार रेल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह भविष्य के लिए मजबूत

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
परिवहन कार्य

मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), मध्य रेल, सोलापुर के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठानों/ठेकेदारों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती हैं। **निविदा सूचना क्रमांकः GEM/2026/B/7340320 dated: 13.03.2026; कार्य का नाम स्थान सहितः** सोलापुर कोचिंग डिपो से माटुंगा वर्कशॉप, परेल वर्कशॉप या भारतीय रेलवे पर किसी अन्य नामित वर्कशॉप तक पहियों सहित असेंबल की गई बोगियों के परिवहन का संविदा कार्य, उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ खुले फ्लैट ट्रक में जेम के माध्यम से किया जाएगा। **निविदा कार्य पद्धतिः** दो पैकेट सिस्टम, **कार्य की औसत लागतः** रु. 2,39,81,299.25, **निविदा प्रपत्र मूल्यः** रु. Nil, **कार्यालय का पता, जहां से निविदा प्रपत्र खरीदे जा सकते हैंः** मंडल रेल प्रबंधक (यांत्रिक), मध्य रेल, सोलापुर; **जमा करने योग्य बयाना रकमः** रु. 2,69,910/-, **कार्य की समापन अवधिः** तीन साल कार्य की प्रारंभ की तिथि से, **निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समयः** 06.04.2026 को 10:00 बजे, **निविदा बक्शा खुलने की तिथि एवं समयः** 06.04.2026 को 10:30 बजे, **वेबसाइट विवरण एवं सूचना बोर्ड लोकेशन जहां से निविदा के संपूर्ण विवरण देखे जा सकते हैंः** www.gem.gov.in

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता,
DE/Sur-06 मध्य रेलवे, सोलापुर

सुरक्षित यात्रा करें,
फुटबोर्ड पर यात्रा न करें

पश्चिम रेलवे
अहमदाबाद मंडल

लेवल क्रॉसिंग का हटाना

ई- निविदा सूचना संख्या 29 वर्ष 2025-26 ई-निविदा संख्याः DRM-ADI-216-2025-26

कार्य का नाम : Sr. DEN (NW)-ADI के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, गांधीधाम और न्यू भुज सेक्शन के बीच, लेवल क्रॉसिंग संख्या 13 Km 20/8-9, 16 Km 26/9-27/0,19 Km 36/0-1, और 20 Km 40/3-4 को, उनके स्थान पर रोड अंडर ब्रिज बनाकर हटाना। **अनुमानित लागतः** ₹ 43,42,59,683.07 **EMD राशिः** ₹ 23,21,300.00 **ई-निविदा बंद होने की तिथि दिनांकः** 07/04/2026 समय 15:00 बजे **कार्यालय का पताः** वरि. मंडल इंजीनियर (सम.)-अहमदाबाद, डी.आर.एम. ऑफिस, चामुंडा ब्रिज के पास, नई स्वदेशी मिल के सामने, नरोडा रोड, अमदुपुरा, अहमदाबाद-382345 **ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइटः** www.ireps.gov.in

ADI 311

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे द्वारा 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली 16 उपनगरीय सेवाओं का 15-डिब्बों में परिवर्तन

15-डिब्बों वाली सेवाओं की कुल संख्या बढ़कर होगी 227

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए वहन क्षमता बढ़ाने एवं अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2026 से 12-डिब्बों वाली मौजूदा 16 उपनगरीय सेवाओं को 15-डिब्बों वाली सेवाओं में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तार का उद्देश्य ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि कर बढ़ती यात्री संख्या को समुचित रूप से समायोजित करना है। इससे ट्रेनों में भीड़भाड़ कम करने तथा दैनिक यात्रियों की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन अतिरिक्त 15-डिब्बों वाली सेवाओं के शुरू होने के बाद उनकी कुल संख्या 211 से बढ़कर 227 हो जाएगी। हालांकि, उपनगरीय सेवाओं की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह 1414 ही रहेगी। बढ़ाई जा रही 16 सेवाओं में से 8 सेवाएं पीक आवर्स में (प्रातःकालीन पीक में 4 तथा सायंकालीन पीक में 4) परिचालित होंगी।

यह पहल पश्चिम रेलवे की सुरक्षित, कुशल एवं यात्री-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे मुंबई की जीवनरेखा और अधिक सुदृढ़ होगी। विस्तृत सूची परिशिष्ट-I में संलग्न है।

राज्य विश्वविद्यालयों में 'स्कूल-कनेक्ट' और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए

स्वावलंबन से जुड़ी पहलें गंभीरता से लागू हों- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

मुंबई। राज्य के राज्यपाल तथा सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जिष्णु देव वर्मा ने पदभार संभालने के बाद पहली बार मंगलवार को मुंबई स्थित लोक भवन से ऑडियो-दृश्य माध्यम के जरिए राज्य के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से संवाद किया। राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि वे अपने विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय रैंकिंग बेहतर करने के लिए समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित करें।

राज्य के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों को स्कूलों के साथ संपर्क बढ़ाना चाहिए और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस संबंध में राज्यपाल ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय 'स्कूल-कनेक्ट' कार्यक्रम के अंतर्गत नवोन्मेषी गतिविधियां लागू करें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लागू करते समय नए और परंपरागत ढांचे से अलग विचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया कि महिला सशक्तिकरण और कौशल शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए शुरू की गई 'स्वयंसिद्धा' पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों को इसे गंभीरता से लागू करना चाहिए। विश्वविद्यालयों ने लोक भवन को बताया कि 'स्कूल-कनेक्ट' और 'स्वयंसिद्धा' कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी दी जा रही है और इसकी समीक्षा लोक भवन द्वारा की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि इन कार्यक्रमों की त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से लोक भवन को भेजी जाए।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि इन दोनों पहलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को पदक या ट्रॉफी देकर सम्मानित करने पर भी विचार किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिन विश्वविद्यालयों की पहलें सफल सिद्ध होंगी, उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वह जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. प्रशांत नरनवरे ने विश्वविद्यालयों द्वारा लागू की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय रैंकिंग, महिला सशक्तिकरण, स्व-रोजगार पहल, कौशल विकास तथा 'स्कूल-कनेक्ट' कार्यक्रम आदि विषयों की जानकारी प्रस्तुत की।

नशे के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' नीति लागू की जाएगी; अपराधियों की संपत्ति भी जब्त होगी– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई।नागपुर शहर के मोती बाग क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद राज्य सरकार नशे के विरुद्ध 'शून्य सहनशीलता' नीति लागू करेगी। ऐसे अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी संपत्तियों को जब्त करना भी शामिल होगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान सभा में दी।

सदस्य प्रवीण डटके ने मोती बाग क्षेत्र में नशीले पदार्थों के तस्करों के घरों पर छापेमारी के दौरान गांजा और अवैध हथियार मिलने के संबंध में प्रश्न उठाया था। इस चर्चा में विकास ठाकरे, विक्रम पचपुते और डॉक्टर नितिन राउत ने भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने बताया कि इस मामले में सामाजिक अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है और आगे कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

यदि किसी प्रकार का अवैध निर्माण पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नगर निगम के माध्यम से नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा।

भविष्य में ऐसी घटनाएँ होने पर संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

नागपुर पुलिस ने 'ऑपरेशन थंडर' के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए पिछले 11 महीनों में 907 अपराधों का पर्दाफाश किया है। इन अभियानों में लगभग 1254 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है।

राज्य में नशा विरोधी अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 31 अगस्त 2023 को नशा विरोधी विशेष बल की स्थापना की गई है। इस व्यवस्था को राज्य के सभी पुलिस थानों तक विस्तारित किया गया है तथा नए पदों की सृजना करके इसे और मजबूत बनाया गया है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के साथ समन्वय तथा खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान से अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई संभव हो रही है। नशे से जुड़े मामलों में केवल अपराध दर्ज करने पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, बल्कि आगे और पीछे जुड़े पूरे तंत्र को खोजकर उसे समाप्त करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही यदि कोई पुलिस कर्मी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपराधों में शामिल पाया जाता है, तो उसे केवल निलंबित नहीं बल्कि सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में नाबालिगों का उपयोग किया जाना एक गंभीर विषय है। इसके लिए ऐसे अपराधों में कानूनी आयु सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

खडकवासला-फुरसुंगी सुरंग परियोजना का कार्य तेज़; पुराने नहर के पुनः उपयोग पर विचार– जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। खडकवासला-मुलशी क्षेत्र में प्रस्तावित खडकवासला-फुरसुंगी भूमिगत सुरंग परियोजना का कार्य तेज गति से प्रगति पर है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2,000 करोड़ रुपये है। यह जानकारी जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने विधान सभा में दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के साथ-साथ खडकवासला बांध से निकलने वाली लगभग 30 से 32 किलोमीटर लंबी पुरानी नहर के पुनः उपयोग के संबंध में भी सरकार नीति तय करेगी।

विधान सभा में सदस्य अधिवक्ता राहुल कुल ने खडकवासला-फुरसुंगी सुरंग परियोजना, चिबड़ भूमि से संबंधित नीति, टाटा पावर से पानी प्राप्त करने तथा उजनी बांध के बैकवाटर क्षेत्र में बैराज निर्माण के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे। इस पर जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने उत्तर दिया। इस चर्चा में सदस्य विजय शिवतारे, विक्रम पचपुते आदि ने भी भाग लिया।

मंत्री विखे-पाटिल ने बताया कि पुरानी नहर के किनारे लगभग 370 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। जल संसाधन विभाग ने उस क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने और भूमि को सुरक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया है। सुरंग का कार्य अगले दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद निचले क्षेत्रों के किसानों को भी

पानी उपलब्ध होगा। नहर के उपयोग के संबंध में एक स्पष्ट नीति तैयार की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मुलशी क्षेत्र के टाटा बांध से पानी उपलब्ध कराने के संबंध में टाटा पावर के साथ सरकार की बातचीत चल रही है और उन्होंने सिद्धांत रूप से पानी देने पर सहमति व्यक्त की है। सरकार का प्रयास है कि कम से कम 7 से 8 टीएमसी पानी उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में अगले दो से तीन महीनों में ठोस निर्णय लिया जाएगा।

मंत्री विखे-पाटिल ने कहा कि कोपा बांधों को बैराज में बदलने की नीति तय कर ली गई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दौंड, श्रीगोंदा और कर्जत तालुकों के पिछड़े क्षेत्रों के गांवों में पानी की कमी न हो, इसके लिए एक बड़े बैराज के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। लाभ क्षेत्र से बाहर की चिबड़ भूमि के संबंध में सरकार ने पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसका क्रियान्वयन अगले एक से दो महीनों में शुरू होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि पुरंदर उपसा सिंचाई योजना में पानी के वितरण को लेकर किसी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए संबंधित विधायकों और विभागों के साथ बैठक कर समन्वय से समाधान निकाला जाएगा। साथ ही डिंबे बांध से संबंधित लंबित सुरंग परियोजना को भी जल्द मंजूरी देकर कार्य शुरू किया जाएगा।

हिंगणा औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा– राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। नागपुर जिले के हिंगणा औद्योगिक क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को पट्टे देने के मामले में राज्य सरकार ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक ने विधान सभा में कहा कि इस विषय को औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा।

विधायक समीर मेघे ने औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन गांवों में सन् 1980 से पहले किए गए अतिक्रमण वाली जमीन तथा वहाँ रहने वाले नागरिकों को आवासीय भूखंड देने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सुझाव रखा था।

राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक ने बताया कि औद्योगिक विकास निगम के नियमों में आवासीय पट्टों के आवंटन या नियमितीकरण के लिए कोई प्रावधान अथवा नीति नहीं है। इसलिए निगम सीधे तौर पर पट्टा प्रदान नहीं कर सकता।

उन्होंने कहा कि सन् 2016 में तत्कालीन पालक मंत्री की उपस्थिति में हुई बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि औद्योगिक विकास निगम यह जमीन राजस्व विभाग को दे और उसके बदले में राजस्व विभाग औद्योगिक विकास निगम को दूसरी जमीन उपलब्ध कराए। राजस्व विभाग ने पोही गांव में 73.69 हेक्टेयर भूमि दिखाई थी, लेकिन वह जमीन औद्योगिक उपयोग के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त न होने के कारण यह प्रस्ताव लंबित रह गया।

राज्य मंत्री इंद्रनील नाईक ने कहा कि पट्टे के आवंटन के लिए नई नीति बनाने का विषय औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाएगा। यदि राजस्व विभाग उचित मूल्यांकन और उपयोग के लिए उपयुक्त दूसरी जमीन उपलब्ध कराता है, तो औद्योगिक विकास निगम को यह जमीन राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बाद राजस्व विभाग अपने नियमों के अनुसार पट्टे के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।

गरीब मरीजों के लिए आरक्षित बिस्तर उपलब्ध न कराने पर ग्लोबल अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई

अतिरिक्त एफएसआई की छूट भी समाप्त की जाएगी– राज्य मंत्री माधुरी मिसाल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल द्वारा गरीब मरीजों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत बिस्तर उपलब्ध न कराने पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और अस्पताल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न करने के कारण अस्पताल को दी गई अतिरिक्त एफएसआई की रियायत भी वापस ली जाएगी, यह जानकारी राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने विधान सभा में दी।

विधायक अजय चौधरी ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि परेल स्थित ग्लोबल अस्पताल द्वारा मुंबई महानगरपालिका के भवन नियमों के उल्लंघन और गरीब मरीजों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत बिस्तर पिछले 15 वर्षों से उपलब्ध न कराने के मामले में राज्य सरकार उचित कदम उठाए। यह मांग स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी की गई थी।

इस चर्चा में योगेश सागर और अनंत (बाला) नर ने भी भाग लिया।

राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया कि अस्पताल को मंजूरी देते समय यह शर्त रखी गई थी कि 15 प्रतिशत बिस्तर महानगरपालिका द्वारा निर्धारित दरों पर गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन यह देखा गया है कि संबंधित अस्पताल इस शर्त का पालन नहीं कर रहा है।

इस पृष्ठभूमि में अस्पताल के नवीनीकरण कार्य को रोक दिया गया था, हालांकि कानूनी प्रक्रिया के कारण अस्पताल को कुछ मरम्मत कार्य करने की अनुमति मिल रही है।

अस्पताल के तीसरे विंग के निर्माण की अनुमति अस्वीकार कर दी गई है। साथ ही कुछ मंजिलों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र भी नहीं दिया गया है। शेष निर्माण कार्य के लिए अनुमति न देने का निर्णय लिया गया है और आवश्यकता के अनुसार संबंधित मंजिलों का कब्जा लेने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में संबंधित अधिकारियों की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने बताया।

ज्ञान भारतम् परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हस्तलिपि सर्वेक्षण अभियान प्रारंभ

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। भारत में हस्तलिखित पांडुलिपियों की अत्यंत समृद्ध विरासत है। पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी इन पांडुलिपियों के माध्यम से ही आगे बढ़ता रहा है। किंतु ये पांडुलिपियां देश के विभिन्न स्थानों पर बिखरी हुई हैं। इन पांडुलिपियों में निहित ज्ञान को एकत्रित कर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ज्ञान भारतम् परियोजना की योजना बनाई है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की मूल्यवान पांडुलिपि धरोहर का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और प्रसार करना है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही इस महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम् परियोजना के अंतर्गत 16 मार्च 2026 से देशव्यापी हस्तलिपि सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है।

संघीय बजट 2025 में घोषित इस योजना के अंतर्गत देशभर की शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों, धार्मिक संस्थानों और निजी संग्राहकों के सहयोग से एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की खोज और पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जुड़ी पांडुलिपियों का राष्ट्रीय डिजिटल अभिलेखागार बनाने का भी केंद्र सरकार का उद्देश्य है, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रक्रिया में पांडुलिपियों का स्वामित्व संबंधित संस्था, पुस्तकालय या निजी संग्राहक के पास ही रहेगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इन पांडुलिपियों को राज्य सरकार को सौंपना चाहता है, तो सरकार उन्हें स्वीकार करेगी।

इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य की विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पांडुलिपि संग्रहालयों और विद्वानों के सहयोग से इस अभियान को लागू किया जाएगा।

महाराष्ट्र में इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं क्लस्टर केंद्र और स्वतंत्र केंद्र के रूप में कार्य करेंगी–

कवि कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, नागपुर – क्लस्टर केंद्र

भांडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान, पुणे – क्लस्टर केंद्र

आनंद आश्रम संस्थान, पुणे – स्वतंत्र केंद्र

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, पुणे – स्वतंत्र केंद्र

महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार संचालनालय, मुंबई को इस परियोजना के लिए राज्य स्तरीय नोडल संस्था नियुक्त किया गया है और इसके निदेशक सुजीत कुमार उगले राज्य नोडल अधिकारी होंगे। इसके साथ ही मराठी भाषा विकास संस्थान की उपनिदेशक अंजली धमाल तथा मराठी भाषा विभाग के अभिजात मराठी भाषा प्रकोष्ठ को सह-नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस सर्वेक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम्' नामक एक मोबाइल अनुप्रयोग विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से पांडुलिपियों का क्षेत्रीय मूल्यांकन, सत्यापन और दस्तावेजीकरण किया जाएगा।

इस अभियान के तहत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिलों में जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जिला स्तरीय समिति गठित करें तथा मंदिरों, मठों, धार्मिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थाओं और निजी संग्राहकों को इस सर्वेक्षण में शामिल करें।

इस सर्वेक्षण अभियान में शैक्षणिक संस्थाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, संस्कृत विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, शोधकर्ताओं, पारंपरिक विद्वानों के साथ-साथ राष्ट्रीय छात्र सेना, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, विद्यार्थियों और विरासत संरक्षण संगठनों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है।

इस अवसर पर यह अपील की गई है कि यदि किसी के पास पांडुलिपियां उपलब्ध हैं तो वे उनकी जानकारी ज्ञान भारतम् मोबाइल अनुप्रयोग पर अपलोड करें और इस राष्ट्रीय कार्य में सहभागी बनें।

रेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि

वडोदरा मंडल द्वारा रेल अवसंरचना को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आनंद-गोधरा खंड के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग संख्या 54ए पर रिलीविंग गर्डर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।

पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इंफ्रा का यह महत्वपूर्ण कार्य दिनांक 16 मार्च, 2026 को अप लाइन तथा 17 मार्च, 2026 को डाउन लाइन पर नियोजित 3 घंटे के ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान कुशलतापूर्वक संपन्न किया गया। कार्य के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया, जिससे यातायात संचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। उक्त अवसंरचना कार्य के निष्पादन में 500 टन क्षमता वाली अत्याधुनिक क्रेन का उपयोग किया गया, जिससे गर्डर लॉन्च अत्यंत सटीकता एवं सुरक्षित ढंग से किया जा सका। इस कार्य की समयबद्ध एवं सफल पूर्णता वडोदरा मंडल की तकनीकी दक्षता, सुनियोजित कार्यप्रणाली तथा प्रतिबद्धता का परिचायक है। वडोदरा मंडल निरंतर रेल अवसंरचना के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं विश्वसनीय सेवाएं प्रदान की जा सकें।

रबी मौसम में ई-फसल निरीक्षण पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाई गई,31 मार्च तक बढ़ाया गया समय– राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान सभा में घोषणा की कि रबी मौसम 2025-26 के लिए सहायक स्तर पर किया जा रहा ई-फसल निरीक्षण पंजीकरण अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

महाराष्ट्र विधान सभा नियम 47 के अंतर्गत दिए गए वक्तव्य में मंत्री बावनकुले ने बताया कि राज्य में वर्तमान में डिजिटल फसल सर्वेक्षण अनुप्रयोग के माध्यम से ई-फसल सर्वेक्षण पंजीकरण किया जा रहा है। राज्य में रबी मौसम 2025-26 के लिए 10 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक किसानों के स्तर पर फसल पंजीकरण शुरू किया गया था।

हालांकि अब तक फसल सर्वेक्षण क्षेत्र का केवल 55.69 प्रतिशत ही पंजीकरण हो पाया है। वर्तमान प्रगति की गति को देखते हुए यह प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी होना संभव नहीं था। इसलिए

यह सुनिश्चित करने के लिए कि फसल पंजीकरण न होने के कारण कोई भी किसान प्राकृतिक आपदा सहायता, फसल बीमा और फसल ऋण जैसी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, सहायक स्तर पर किए जाने वाले पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। मंत्री बावनकुले ने यह भी बताया कि राज्य के सभी जिला अधिकारियों को रबी मौसम के लिए 100 प्रतिशत ई-फसल निरीक्षण पंजीकरण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीड जिले में फर्जी मजदूर प्रकरण की जांच के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई– श्रम मंत्री अधिवक्ता आकाश फुंडकर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई, 17 तारीखः श्रम मंत्री अधिवक्ता आकाश फुंडकर ने विधान सभा में आश्वासन दिया कि बीड जिले में फर्जी मजदूर प्रकरण की स्वतंत्र अधिकारी से गहन जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ शत-प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी अपील की।

मंत्री फुंडकर ने बताया कि श्रम विभाग ने सतर्कता दलों के माध्यम से राज्यभर में 46 स्थानों पर मामले दर्ज किए हैं। बीड जिले के मामले की भी विस्तृत जांच की जाएगी।

विधान सभा में सदस्य सुरेश धस ने निर्माण कामगार कल्याण मंडल के अंतर्गत मार्च 2020 से फरवरी 2026 के बीच फर्जी मृत मजदूर दिखाकर करोड़ों रुपये के गबन के आरोपों के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था।

अपने उत्तर में श्रम मंत्री अधिवक्ता फुंडकर ने कहा कि राज्य के कुछ स्थानों पर फर्जी एजेंट झूठे दस्तावेज, नकली हस्ताक्षर और मुहरों का उपयोग कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी और दोषी अधिकारियों, संबंधित संस्थाओं या अन्य किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पहले श्रमिक पंजीकरण प्रक्रिया ऑफलाइन थी, जिसके कारण ऐसी अनियमितताओं की संभावना बनी रहती थी। इस कमी को दूर करने के लिए अब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है और इसमें बायोमेट्रिक प्रणाली भी शामिल की गई है, जिससे धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

मंत्री फुंडकर ने बताया कि 2020 से 2026 के बीच बीड जिले में 115 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से एक दुर्घटनाजनित मृत्यु का आवेदन सही पाया गया है, जबकि शेष 114 मामलों की जांच जारी है। अब तक 53 मामलों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जबकि बाकी मामलों का सत्यापन अभी जारी है।

उमरखेड़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए राज्य सरकार सकारात्मक– लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई। यवतमाल जिले के उमरखेड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उमरखेड़ और महागांव तालुकों में मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण के संबंध में लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने विधान सभा में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में बढ़ने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए यहाँ नए कार्य किस प्रकार किए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। विधायक किसान वानखेड़े ने क्षेत्र की सड़कों की खराब स्थिति और उन्हें जल्द चौड़ा करने की आवश्यकता का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्री ने विभाग की स्थिति स्पष्ट की। मंत्री श्री भोसले ने बताया कि लोक निर्माण विभाग सड़कों के चौड़ीकरण के लिए सकारात्मक है। वर्तमान में 513 और 51 डी मार्गों पर कार्य प्रगति पर है। बड़े शहरों या गांवों में 10 मीटर चौड़ी सड़क तथा दोनों ओर 3 मीटर पक्का मार्ग बनाने का प्रस्ताव है।उन्होंने कहा कि यदि चल रहे कार्यों में तकनीकी परिवर्तन किए जाते हैं तो भूमि अधिग्रहण जैसी समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हो सकती है।

सम्पादकीय

सत्ताधारी दलों की रणनीति और मतदाता सूची की उलझन चुनावों के पहले बड़े दांव

निर्वाचन आयोग की ओर से चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख तय किए जाने के साथ ही अब वहां नए जन प्रतिनिधियों को चुने जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके समांतर यह बहस का विषय है कि जिन जगहों पर अभी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के बाद अंतिम सूची तैयार होना बाकी है, वहां यह कैसे सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिले।

गौरतलब है कि रविवार को पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी गई। पश्चिम बंगाल में दो चरण और बाकी जगहों पर एक चरण में चुनाव होंगे। इसी क्रम में अलग-अलग राज्यों की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब इन जगहों पर चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। मगर कई बार राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की घोषणा पहले ही कर देते हैं। अब तक इस प्रवृत्ति पर कोई ठोस नियंत्रण नहीं हुआ है।

ज्यादातर मौकों पर चुनाव के ठीक पहले विशेष घोषणाएं और मुफ्त की सौगात देने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच होड़-सी लग जाती है। इसमें सत्ताधारी दल को ऐसी घोषणा करने और तुरंत अमल करने का बेहतर मौका मिलता है।

असम में महिलाओं, विद्यार्थियों और चाय बागानों में काम करने वालों के लिए नकद भुगतान योजनाओं के जरिए भाजपा ने मतदाताओं के एक बड़े हिस्से का समर्थन हासिल करने के लिए मजबूत दांव खेला। हालांकि कई स्थानीय मुद्दों और विवादों पर उसे विपक्ष से चुनौती मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव की घोषणा के ठीक पहले पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में पांच सौ रुपए की बढ़ोतरी के अलावा कुछ अन्य घोषणाएं कीं। ऐसे फैसलों को जनहित में बताया जाता है, लेकिन विचित्र यह है कि मतदाताओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं की याद सत्ताधारी पार्टियों को चुनाव सिर पर आने के बाद ही आती है।

इन चुनावों में सबसे अहम मुद्दा यह उभरा है कि कई जगहों पर मतदाता सूची का काम अभी अंतिम स्वरूप में नहीं पहुंचा है। क्या बहुत सारे लोग भी वोट देने से वंचित रह जाएंगे, जिन्हें वैध मतदाता माना जाएगा? पश्चिम बंगाल में इस बार मतदाता सूची में बदलाव पर खासा विवाद है। एसआइआर के बाद अंतिम सूची से लगभग छियासठ लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं करीब साठ लाख मतदाताओं के नाम अभी भी विचाराधीन सूची में हैं।

मतदाता सूची से हटाए गए नाम, उन पर उठी आपत्तियां, सुधार के दावे आदि तमाम विवाद चुनाव की तारीख से पहले निपटा लिए जाएंगे या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। अगर वैध मतदाता भी मतदान से वंचित रह गए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। मगर यह भी जरूरी है कि सभी सीटों पर हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई भी अपनी भागीदारी के अधिकार से वंचित न हो।

अगले दस साल में बीमारियां खत्म कर देगी एआइ, 2030 तक इंसानी क्षमता से तेज चलने वाली मशीनें आ जाएंगी

इसमें कोई दोराय नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि यानी एआइ एक दोधारी तलवार है, जिसे सही नियमों और नैतिक दिशा-निर्देशों के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो मानवता के लिए वरदान है। दूसरी तरफ इसकी अनियंत्रित वृद्धि सामाजिक और नैतिक ताने-बाने के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। क्या मानव समाज में एआइ की सच में इतनी जरूरत है?

मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार किया अपने काम को सरल बनाने और कम समय में अधिक काम पूरा करने के लिए, ताकि बचे हुए समय में अपनों के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। मगर यह नहीं सोचा गया होगा कि एक दिन मशीनें ही मनुष्यों का स्थान लेने लगेंगी और उनके अस्तित्व के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चल रहा था, एक खुशहाल जीवन जी रहा था। जैसे ही उसने विकसित तकनीक का प्रयोग करके प्रकृति के नियम को तोड़ने और तकनीकी व आभासी वातावरण बनाने की कोशिश शुरू की, समाज अनेक तरह के जोखिमों का सामना करने लगा।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक डेमिस होसाबिस का तर्क है कि जहां एआइ के विकास से संभावनाएं बढ़ी हैं, वहीं उसके खतरे भी उभरे हैं। एआइ की दौड़ में कुछ देश या कंपनियां सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर सकती हैं। ऐसा करने पर यह तकनीक मानवता के लिए विनाश का कारण बन सकती है। उनका तर्क है कि एआइ को बच्चों की तरह ही नैतिकता और इंसानियत सिखाने की जरूरत है। वे चाहते हैं कि ऐसी एआइ विकसित हो, जो न सिर्फ बुद्धिमान हो, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार भी हो।

माना जा रहा है कि 2030 तक इतना सोचने वाली मशीन आ जाएगी, जो इंसानी क्षमता से अधिक तेज और ज्ञानवान होगी। वह हमारे आसपास की दुनिया को गहराई से समझेगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलमिल जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि एआइ अगले दस साल में बीमारियों को खत्म कर देगा। सवाल यह है कि प्राकृतिक वातावरण में इतनी बीमारियां तो नहीं थीं, जितनी आज के डिजिटल वातावरण में विकसित हुई हैं, तो क्या ये बीमारियां विकसित तकनीक के अधिक उपयोग के कारण ही उभर रही हैं?

पहले मशीन एक सहायक के रूप में प्रयुक्त होती थी और मुख्य भूमिका मनुष्य की होती थी, लेकिन अब मुख्य भूमिका में एआइ (विकसित मशीन) है और मनुष्य केवल सहायक की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में मनुष्य का शरीर और दिमाग, दोनों ही शिथिल पड़ने लगते हैं और अनेक तरह की बीमारियों का घर बन जाते हैं।

यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक करोड़ों नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि एआइ मनुष्य से अधिक कुशलता से काम कर सकती है। ऐसे में समाज में एक नए प्रकार का विभाजन उभरेगा– श्रेष्ठ बौद्धिक जनसंख्या और कम बौद्धिक जनसंख्या। मशीन मनुष्य से अधिक संपूर्णता से काम करती है, इसलिए लोग उस पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। इस कारण से हर क्षेत्र के विशेषज्ञों और उनके कौशल को चुनौती मिल रही है।

डाक्टर की जगह एआइ बहुत गहनता से मेडिकल रपट की जांच करती है और बीमारी का कारण व निदान बताने लगी है। शिक्षकों की जगह एआइ से पढ़ने में विद्यार्थी अधिक रुचि लेने लगे हैं। वास्तुविद, काउंसलर, फैशन, प्रशिक्षक, कोच, व्यायाम–सभी क्षेत्रों में एआइ ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया है। ऐसे में युवाओं को लगता है कि अब उन्हें परिवार, मित्र या अन्य किसी की जरूरत नहीं है। सभी की कमी एआइ से पूरी की जा सकती है।

एआइ युवा पीढ़ी की विश्लेषण करने और अलग तरह से सोचने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। मसलन, पहले कुछ भी लिखने के लिए सोचना और पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब अधिकांश विद्यार्थी और युवा चैट-जीपीटी पर विषय लिख देते हैं और वह कुछ ही सेकंड में उत्तर तैयार करके दे देता है। यहां तक कि पसंद न आने पर अनेक अन्य विकल्प भी देता है। सवाल यह भी है कि क्या उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं सौ फीसद सही होंगी। यह एक कृत्रिम यंत्र ही है, जो मनुष्य द्वारा निर्मित है।

फिर इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि एआइ का शिक्षा के क्षेत्र पर सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। विशेष रूप से समाज विज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। एआइ ने 'उपयोग के लिए तैयार सामग्री' उपलब्ध कराकर बच्चों को बंधक मस्तिष्क (कैप्टिव माइंड) में बदल दिया है। चाहे कोई 'प्रोजेक्ट' बनाना हो, आवेदन लिखना हो, लेख लिखना हो या फिर किसी शोधार्थी को कोई शोध कार्य करना हो, सभी चैट-जीपीटी और अन्य एआइ ऐप के माध्यम से अपने कार्य को करने लगे हैं।

इससे समय की बचत तो होती है, लेकिन विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता और आलोचनात्मक समझ भी प्रभावित हो रही है। समय अगर किसी उचित काम के लिए बचाया जाना है, तो कुछ हद तक इसे सही कहा जा सकता है, लेकिन बच्चे और युवा उस समय को स्मार्टफोन स्क्रॉल करने, रील बनाने या ऑनलाइन गेम खेलने और यहां तक कि कुछ अपराध में लगा रहे हैं। परिणामस्वरूप छोटी-सी उम्र में ही बच्चे अनेक गंभीर शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि स्मार्टफोन तक ही लोगों का जीवन विश्व सिमट कर रह गया है।

हाल ही में इसरो के एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक ने इसलिए अपनी पत्नी की हत्या कर दी कि 'मेरे मरने के बाद इसकी देखभाल कौन करेगा।' उनकी इकलौती बेटी अमेरिका में बस गई थी, जिससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। इसी तरह मुंबई के एक संभ्रांत इलाके में एक बुजुर्ग दंपति की सड़ी हुई लाश उनके आलीशान बंगले में मिली थी, जिनके दोनों बेटे विदेश में बसने के कारण अपने बुजुर्ग मां-बाप की देखभाल करने में असमर्थ थे। उनके पास अकूत धन-दौलत थी, लेकिन समय नहीं था।

इन घटनाओं में परिवार हर दृष्टि से समृद्ध और संपन्न थे, लेकिन परिवार के सदस्यों में भावनात्मक लगाव और संवादहीनता की स्थिति थी। ऐसी भौतिक संपन्नता और तकनीकी विकास दृष्टि किस काम की, जब बुजुर्ग माता-पिता का अंतिम संस्कार लावारिस की तरह अनजान लोगों द्वारा किया जाए? क्या इसी दिन के लिए लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए अपने जीवन की हर इच्छा को त्याग देते हैं? एआइ निर्देशित मशीन से काम के घंटे कम हो सकते हैं, जिससे लोगों के पास अधिक समय रहता है और जिसे वे अपने परिवार के साथ बिताने में खर्च कर सकते हैं। मगर यह कितना संभव हो पा रहा है? एआइ के तंत्र ने व्यक्तिगत डेटा को सार्वजनिक कर दिया है, जिससे गोपनीयता की समस्या उभर रही है। समाज में आर्थिक असमानताओं में वृद्धि के कारण एआइ तंत्र का लाभ उठाने के लिए लोगों को तकनीकी ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे समाज में अन्य प्रकार की असमानताएं बढ़ सकती हैं।

इसलिए लोगों को एआइ और नवीन तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ इससे होने वाले खतरों से अवगत करना होगा। सरकार या प्रशासन को भी एआइ प्रणालियों के उपयोग को नियंत्रित करना होगा, ताकि वे सुरक्षित और न्यायसंगत बन सके। तकनीक कितनी भी विकसित क्यों न हो जाए, मनुष्य का स्थान नहीं ले सकती।

प्राकृतिक (वास्तविक) बुद्धि में कृत्रिम बुद्धि को विकसित करने की क्षमता है, लेकिन कृत्रिम बुद्धि कभी भी वास्तविक बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर पाएगी और न ही उसे विस्थापित कर सकेगी, लेकिन मानव जीवन के समक्ष खतरे और चुनौतियां जरूर उत्पन्न कर सकती है। इस पर समय रहते नियंत्रण करने की जरूरत है।

महिलाओं की मेहनत को समझना जरूरी, अदालत ने पूछा- क्या घर संभालना 'काम' नहीं है

महिलाएं कामकाजी हों या गृहिणी, उनके श्रम का सम्मान उनके अस्तित्व की सहज स्वीकार्यता से जुड़ा है। हाल के वर्षों में कामकाजी स्त्रियों की उपस्थिति और आर्थिक भूमिका की स्वीकार्यता बढ़ी है। उनकी समस्याओं को समझने की सोच को बल मिला है। वहीं गृहिणियों के श्रम की अनदेखी से जुड़ी पारंपरिक सोच आज भी कायम है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई न्यायिक निर्णयों में घरेलू महिलाओं की भूमिका को समझने और सम्मान देने की बात कही गई।

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की कि गृहिणी को निष्क्रिय मानना घरेलू योगदान की गलत समझ को दर्शाता है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि घरेलू संबंधों में पत्नी के योगदान के आर्थिक मूल्य को कानून में मान्यता दी जानी चाहिए। वर्ष 2012 में हुए विवाह से जुड़े मामले में पत्नी का आरोप था कि 2020 में पति ने उसे और नाबालिग बेटे को छोड़ दिया।

निचली अदालत ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि पत्नी शिक्षित और सक्षम है, लेकिन उसने नौकरी नहीं की। मगर इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग बातें हैं। साथ ही भरण-पोषण के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह भी जोड़ा कि 'गृहिणी' या 'होममेकर' का श्रम कमाने वाले जीवनसाथी को प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है, इसलिए उसकी बेरोजगारी को आलस्य के बराबर मानना अन्यायपूर्ण है।

ये टिप्पणियां स्त्री जीवन के उस आधारभूत पक्ष को संबोधित करती हैं, जिसकी अनदेखी की गई। जबकि स्त्रियों की इस भागीदारी में शारीरिक-मानसिक श्रम ही नहीं, भावनात्मक मोर्चे पर की गई मशक्कत भी होती है। बच्चों के पालन-पोषण से लेकर बुजुर्गों की संभाल तक संवेदना और संयम का यह परिश्रम हमारी पारिवारिक व्यवस्था को थामे हुए है। गृहिणी के रूप में अपने दायित्वों को संभालने वाली एक पूरी पीढ़ी आज की कामकाजी बहू-बेटियों के जीवन की बुनियाद बनाने वाली रही हैं।

वैवाहिक जीवन में भी घरेलू जिम्मेदारियां उठाने वाली महिलाएं जीवनसाथी का जीवन आसान बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विचारणीय है कि मौद्रिक मूल्य न आंके जाने की वजह से महिलाओं की भूमिका के प्रति भेदभाव होता आया है। अपने घर की खेती-किसानी में हाथ बंटाने वाली महिला कृषक हो या सामाजिक-पारिवारिक रिश्तों को सहेजने में जीवन खपा देने वाली आम स्त्रियां, उनके योगदान की उपेक्षा का रवैया देश के हर हिस्से में रहा है।

ऐसे में अदालत की यह टिप्पणी अहम हो जाती है कि कानून को केवल आय को ही नहीं, बल्कि विवाह के दौरान घर और पारिवारिक संबंधों में पत्नी के घरेलू श्रम के योगदान के आर्थिक मूल्य को भी मान्यता देनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल और परिवार के समर्थन का भी आर्थिक मूल्य है, भले ही वह आयकर या बैंक विवरण में दर्ज न हो।

इसीलिए कानून यह सुनिश्चित करे कि परिवार निर्माण में समय और श्रम का निवेश करने वाला जीवनसाथी असहाय न रह जाए। विडंबना है कि स्त्रियों की इस श्रमशील भूमिका के प्रति सम्मान का भाव आज भी नदारद है। यहां तक कि उनके अस्तित्व को ही नकार देने का भाव दिखता है।

कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने भी कहा था कि गृहिणी का काम वेतन घर लाने वाली महिला से कम नहीं होता। परिवार में भले ही उसके योगदान का मौद्रिक आकलन नहीं किया जा सकता, पर अपनों की देखभाल करने वाली इस भूमिका का विशेष महत्त्व है।

गौरतलब है कि 2006 में उत्तराखंड में हुई एक दुर्घटना में महिला की मौत हो गई थी। महिला जिस वाहन से यात्रा कर रही थी, उसका बीमा न होने की वजह से न्यायाधिकरण ने महिला के परिवार को ढाई लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का फैसला किया था। दुखद पक्ष यह रहा कि महिला को मिलने वाली बीमा राशि को न्यायाधिकरण ने कम आंका, क्योंकि महिला गृहिणी थी। इसलिए मुआवजा जीवन प्रत्याशा और न्यूनतम अनुमानित आय पर तय किया गया था। केरल उच्च न्यायालय द्वारा भी केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को एक सड़क हादसे में पीड़िता को इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार करने पर फटकार लगाई जा चुकी है कि पीड़िता एक गृहिणी है। गृहिणी होने की वजह मुआवजे का पात्र नहीं माने जाने के तर्क को अदालत ने अपमानजनक और समझ के परे बताते हुए कहा था कि हादसे के लिए मुआवजा एक गृहिणी और कामकाजी महिला के लिए समान होना चाहिए। सशक्त और सजग स्त्रियों का समाज बनाने वाले दावों और वादों के बीच घर-परिवार में स्त्री के परिश्रम की अनदेखी का बर्ताव दुखद है। जबकि गृहिणी या घर को घर बनाने वाली स्त्री की भागदौड़ से ही स्वजनों-परिजनों के जीवन की गति जुड़ी है। उनसे मिली देखभाल नई पीढ़ी को सपने साधने का धरातल देती है। उनकी मौजूदगी से वरिष्ठजनों को सुरक्षा-संभाल का भरोसा मिलता है।

बावजूद इसके आर्थिक उपार्जन का आकलन करने वाला समाज यह समझने का प्रयास नहीं करता कि यह भागीदारी अनमोल है। अफसोस कि सरकारी नीतियों और योजनाओं में भी गृहिणियों के लिए कहीं कोई विशेष प्रावधान नजर नहीं आता। जबकि वेतन चुकाकर न तो ऐसी जिम्मेदारियां किसी को दी जा सकती है और न ही कोई आत्मीय भाव संग ऐसे दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2021 की रपट बताती है कि विश्व में महिलाएं अवैतनिक घरेलू कार्यों के लिए कुल घंटों का छिहत्तर फीसद समय देती हैं। एशियाई देशों में यह आंकड़ा अस्सी फीसद से भी ज्यादा है। जरूरी है कि गृहिणियों को दूसरों पर निर्भर व्यक्तित्व के रूप में देखने के बजाय उनके श्रम के सम्मान का भाव आए। घर तक सिमटी जिंदगी जी रही महिलाओं को समझने का परिवेश बनाया जाए। उनकी भूमिका के प्रति उपेक्षा का व्यवहार उनका मनोबल तोड़ता है। ऐसे में अपनों की भावनात्मक समस्याओं को समझने वाली घरेलू स्त्रियों को भी समाज और परिवार का संबल मिले।

क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अविवाहित इंजीनियर पुत्र निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी लॉन्चिंग से बिहार की राजनीति में दूरगामी असर पड़ना लाजिमी है। चूंकि वह अपने प्रगतिशील और यशस्वी पिता की प्रगतिशील समाजवादी सियासत को संभालेंगे, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट हैं। वह यह कि अब तीन बड़े स्तरों पर इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ेगा- सत्ता संतुलन, जेडीयू की आंतरिक राजनीति और राज्य की व्यापक सियासी प्रतिस्पर्धा। इसके अलावा कुछ मौलिक सवाल भी उभरेंगे, जिनकी चर्चा पहले लाजिमी है। स्वाभाविक सवाल है कि क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे? हालांकि इसका जवाब गुजशते वक्त की कोख में पल रहा है, जो समय के साथ स्पष्ट होता जाएगा।

पहला यह कि उनके पिता नीतीश कुमार अब शारीरिक रूप से अस्वस्थ होकर 'विलासितापूर्ण' सदन राज्यसभा की ओर रुखसत हो चुके हैं, जबकि बिहार के पुनर्निर्माण के उनके सपने अभी भली भांति पूर्वक जवान भी नहीं हो पाए हैं। इसलिए उन्हें उचित नीतिगत पोषण प्रदान करते हुए जवान करने की जिम्मेदारी अब टीम निशांत कुमार की होगी।

कहना न होगा कि पहले 20 साल तक यानी 1985 से 2025 तक नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत संघर्ष की राजनीति की और बाद के 20 वर्षों तक यानी 2005 से 2025 उन्होंने सत्ता संघर्ष की राजनीति की। इसी कशमकश में बिहार के पुनर्निर्माण के उनके सपने वैचारिक कुपोषण, प्रशासनिक धूर्तता के शिकार हो गए और पूरी तरह से जवान नहीं हो पाए।

दूसरा यह कि जनता दल यूनाइटेड की सहयोगी पार्टी भाजपा भले ही राष्ट्रीय समाजवादी राजनीति की तरह ही सूबाई समाजवादी राजनीति के प्रतिबिंब जदयू को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ चुकी है, लेकिन पुनः सियासी धोबिया पाट पर राजनीतिक चोट देते हुए जदयू को देश-प्रदेश में पुनः बड़े भाई का दर्जा दिलवाने के सारे दारोमदार अब निशांत कुमार के कंधे पर होंगे। संदेश स्पष्ट है कि बड़े सपने देखेंगे तो उड़ीसा के नवीन पटनायक की तरह सफलतापूर्वक भविष्य में राज करेंगे, अन्यथा चिराग पासवान की तरह बीजेपी के आगे सियासी दुम हिलाते नजर आएंगे। यदि ऐसा हुआ तो यही समझा जाएगा कि बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार ने अपनी पुत्र को समुचित राजनीतिक शिक्षा दिए ही उनकी लॉन्चिंग करवा दी। कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के जेहन में उठ भी रहे हैं।

तीसरा यह कि जेडीयू और उसके सत्ता समीकरण पर इसका सीधा असर पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और संभावित नेतृत्व परिवर्तन के साथ निशांत को डिप्टी सीएम/मुख्य चेहरा बनाने की तैयारी है, जिससे जेडीयू में नेतृत्व का खालीपन भरने की कोशिश होगी। यह कदम बीजेपी-जेडीयू गठबंधन में निरंतरता का संदेश देगा कि नीतीश भले पटना से दिल्ली शिफ्ट हों, पर 'उनका आदमी/परिवार' सत्ता में रहेगा, जिससे अचानक अस्थिरता की संभावना घटेगी। लेकिन इसके दूरगामी असर नकारात्मक भी हो सकते हैं।

चौथा यह कि जेडीयू की आंतरिक राजनीति भी इस घटनाक्रम से प्रभावित होगी। ऐसा इसलिए कि जेडीयू के कई एमएलए-एमपी ने खुले तौर पर मांग की कि निशांत ही पार्टी को 'एकजुट रख सकते हैं', जो यह दिखाता है कि नेतृत्व संकट से बचने के लिए संगठन परिवारवाद को स्वीकार कर चुका है। इससे पुराने कद्दावर नेताओं के बीच पद-प्रतिष्ठा को लेकर खींचतान बढ़ सकती है क्योंकि अचानक एक नए, राजनीतिक रूप से अनुभवहीन चेहरे को शीर्ष पर लाना वरिष्ठों की महत्वाकांक्षाओं से टकराएगा।

पांचवां यह कि इस बड़े बदलाव से जदयू के वंशवाद बनाम सुशासन की छवि टकराएगी, क्योंकि नीतीश लंबे समय से वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं; और अब बेटे की लॉन्चिंग से उनकी राजनीतिक व वैचारिक साख और 'सुशासन बाबू बनाम पारिवारिक राजनीति' वाली नैरेटिव पर विपक्ष को मजबूत हमला करने का मौका मिलेगा। वहीं, आरजेडी-कांग्रेस सहित विपक्ष इसे 'डबल स्टैंडर्ड' कहकर भुनाएगा, जिससे सामाजिक न्याय बनाम परिवारवाद की पुरानी बहस फिर तेज होगी और यादव-गैर लवकुश ओबीसी-अल्पसंख्यक वोटों की समीक?ण राजनीति और ज्यादा आक्रामक हो सकती है, जिसकी धार नीतीश कुमार और भाजपा मिलकर कुंद कर चुकी हैं।

छठा यह कि जदयू के इस घटनाक्रम का सूबाई युवा और सामाजिक आधार पर भी संभावित प्रभाव पड़ेगा। अब जदयू पार्टी के भीतर से यह तर्क दिया जा रहा है कि निशांत के आने से युवा वोटर और पढ़ा-लिखा मध्यवर्ग जुड़ सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब वे जल्दी ज़मीनी राजनीति सीखकर स्वतंत्र छवि बना पाएं। अभी के लिए उनका पूरा राजनीतिक वैधता पूंजी 'नीतीश के बेटे' होने से आती है; अगर प्रशासनिक या संगठनात्मक क्षमता जल्दी साबित न हुई तो वे सिर्फ प्रतीकात्मक वारिस बनकर रह सकते हैं, जिससे जेडीयू की गिरती सामाजिक पकड़ नहीं रुक पाएगी।

सातवां यह कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग का बिहार की व्यापक सियासत में लंबी अवधि का असर पड़ेगा। निकट भविष्य में यह कदम बीजेपी-जेडीयू सरकार को स्थायित्व देगा, लेकिन मध्यम अवधि में यह तय करेगा कि नीतीश के बाद जेडीयू स्वतंत्र शक्ति बनी रहती है या भाजपा पर और अधिक निर्भर हो जाती है। ऐसा इसलिए कि यदि निशांत कुमार पार्टी के अंदर स्वीकार्यता बना लेते हैं और संगठन पर पकड़ मजबूत कर लेते हैं, तो वे आने वाले चुनावों में जेडीयू को 'पोस्ट-नीतीश' दौर में भी प्रासंगिक रख सकते हैं; वहीं यदि असफल रहे तो बिहार की राजनीति और ज़्यादा द्विध्रुवीय (बीजेपी बनाम आरजेडी-कांग्रेस) हो सकती है और जेडीयू हाशिये पर जा सकता है।

आठवां यह कि निशांत की एंट्री ने नीतीश कुमार के सालों पुराने एंटी वंशवाद नैरेटिव को सीधे काट दिया और बिहार में लगभग सभी बड़े नेताओं के परिवारवाद को एक साथ एक्सपोज़ कर दिया। इससे यह साफ दिखने लगा कि 'वंशवाद विरोध' ज्यादातर नैतिकता नहीं, बल्कि अवसरवादी राजनीति की भाषा थी। इस मुद्दे पर नीतीश का यू टर्न और नैतिकता का संकट खड़ा हो गया है। नीतीश खुद को कर्पूरी ठाकुर की परंपरा का मानते रहे, जो बेटे को राजनीति से दूर रख कर वंशवाद के खिलाफ उदाहरण बताए जाते हैं।

नौवां यह कि, कई दशक तक वे लालू प्रसाद, कांग्रेस और अन्य दलों पर परिवारवाद का हमला बोलते रहे; और अब उसी मॉडल पर अपने बेटे निशांत को सीधे उत्तराधिकारी की तरह आगे कर रहे हैं। जिस तरह से राज्यसभा जाने और बेटे के लिए स्पेस बनाने के लिए उन्होंने राजनीतिक पटकथा लिखी है, उससे उनकी समाजवादी राजनीति पर भी सवाल उठना लाजिमी है। बताया जाता है कि विपक्ष (जैसे ठ्ठ) ने इसे तुरंत पकड़ लिया कि जिसने हमेशा नेपोटिज़्म को कोसा, वही अब 'अपने उत्तराधिकारी को सेट' कर रहा है, यानी नैतिक ऊँचाई ढह गई।

दसवां यह कि बिहार की ओबीसी/दलित 'राजवंशी' राजनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। पहले से ही तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक आदि खुले तौर पर पिता की विरासत संभाल रहे थे। इसी कड़ी में नीतीश पुत्र निशांत की एंट्री के बाद तस्वीर और साफ हो गई कि लगभग हर प्रमुख सामाजिक राजनीतिक धड़े का नेतृत्व अब 'पॉलिटिकल वंशजों' के हाथ में जा रहा है, यानी पूरा सत्ता-संतुलन परिवारों के इर्द गिर्द घूम रहा है।

ग्यारहवां यह कि प्रशांत किशोर व अन्य आलोचकों ने राजनीतिक पाखंड उजागर किया। प्रशांत किशोर ने सीधे सवाल उठाया कि जो नेता जीवन भर वंशवाद के विरोध का दावा करते रहे, वे आज अपने ही बेटे के लिए जगह बना रहे हैं; यानी 'सिद्धांत' दरअसल सत्ता और परिवार के हिसाब से बदलने वाली चीज़ है। वहीं, राजद नेताओं ने भी कहा कि नीतीश अब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं, जिसको वे लालू परिवार की राजनीति में दोष बताते थे; इससे 'हम अलग हैं' वाला दावा कमजोर हो गया।

बारहवां यह कि युवाओं के मुद्दों बनाम राजनीतिक वंश की कशमकश अब तेज होगी। क्योंकि निशांत की लॉन्चिंग बहस के साथ ही बेरोजगारी, पलायन और सुशासन बनाम परिवारवाद जैसे सवाल फिर उभरे हैंः क्या नई पीढ़ी के लिए नेतृत्व का मतलब सिर्फ नेताओं के बच्चे होंगे या आम कार्यकर्ता/युवा भी ऊपर आएंगे? वहीं जदयू और सहयोगी इसे 'नई पीढ़ी का नेतृत्व' कह कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तर्क भी उसी समय कमजोर पड़ जाता है जब टिकट, पद और कुर्सी लगभग पूरी तरह परिवारों में सिमटते दिखते हैं। स्वाभाविक सवाल है कि क्या जदयू में निशांत कुमार की धमाकेदार सियासी एंट्री के राजनीतिक असर दूरगामी होंगे? हालांकि इसका जवाब गुजशते वक्त की कोख में पल रहा है, जो समय के साथ स्पष्ट होता जाएगा।

गौआश्रय स्थल, पशुपालन, कृषि, उद्यान एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का बिंदुवार सीडीओ ने किया समीक्षा

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार के कुशल मार्गदर्शन में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड से कृषि, उद्यान, गौआश्रय स्थल, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की जनपद स्तरीय निगरानी समिति की समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि गोवंशों के लिए हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि तीनों तहसीलों में चारागाह भूमियों पर हरे चारे, बरसीम आदि की बुवाई करवाएं। गौआश्रयों स्थलों के भरण पोषण का भुगतान समय से सुनिश्चित करें साथ ही वहां पर तैनात केयर टेकरों का समय से भुगतान कराए। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक पशु चिकित्सालयों में डॉक्टरों की तैनाती अवश्य करायी जाये, कही केन्द्र बन्द पाया गया तो सम्बन्धित की जबाबदेही तय की जायेगी। साथ ही अस्पतालों की व्यवस्था सुव्यवस्थित कराने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी व खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा गो आश्रय स्थल व पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर बल दिया गया। उन्होंने जनपद के प्रत्येक विकासखंड में न्यूनतम एक वृहद गो संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने हेतु कम से कम एक हेक्टेयर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने पर बल दिया। गो आश्रय स्थल में संरक्षित समस्त गोवंशों के भरण पोषण हेतु समय से डिमांड अपलोड करना, मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना अंतर्गत आवंटित लक्ष्य को पूर्ण किए जाने हेतु इच्छुक पशुपालकों की सुपुर्दगी में गो आश्रय स्थलों से गोवंश दिया जाना, गो आश्रय से संबंधित नामित नोडल अधिकारी द्वारा पाक्षिक निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराना, पशु शवों को समुचित निस्तारण , समस्त गो आश्रय में सुरक्षित गोवंश के भरण पोषण में साइलेज , बरसीम के उपयोग सहित विभिन्न बिंदुओं के प्रगति से अवगत कराया गया।

मुख्य विकास अधिकारी ने

निर्देश दिया कि मोटे अनाज श्री अन्न निर्मित बिस्किट, नमकीन, मिठाई व अन्य खाद्यय प्रदार्थ बनाने वाले एंटरप्रेन्योर का ऑनलाइन आवेदन कराए। फसल बीमा लाभ, फसल बीमा दावा को प्रभावी क्रियान्वित करें। फार्मर रजिस्ट्रेशन में खतौनियों की अशुद्धि के कारण आ रही समस्या एवं जन जागरूकता को भी कराएं।

मुख्य विकास अधिकारी ने कृषि विभाग की समीक्षा में फार्मर रजिस्ट्री के प्रगति बढ़ाने का निर्देश उप कृषि निदेशक को दिया। बैठक में फसल अवशेष प्रबन्धन योजना, मिनी किट का वितरण, फसली ऋण की प्रगति, भूमि संरक्षण की तीनों योजनाओं, प्लांट प्रोटेक्शन आदि बिन्दुओं पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि कुछ नया कार्य कराये। जिससे किसानों की आय में बृद्धि हो।

मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल ने मिलेट्स अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया कि मोटे अनाज सावां, कोंदो , रागी, ज्वार , बाजार , आदि की मिलेट्स अनाजों को दैनिक खान-पान में शामिल करने के लिए प्रेरित करे। जिलाधिकारी ने मछुआ समुदाय के लाभार्थी परक योजनाओं, दुर्घटना बीमा आदि से आच्छादित करने पर बल दिया।

उपनिदेशक कृषि डॉ अश्वनी सिंह द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री प्राथमिकता की योजनाओं के अंतर्गत कृषि रक्षा रसायन डीबीटी , प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियांन पीएम कुसुम सोलर पंप योजना, बीज डीबीटी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने मृदा हेल्थ कार्ड योजना , कृषक उत्पादक संगठन, सब मिशन आन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन , उत्तर प्रदेश श्री अन्न मिलेटस पुनरोदधार कार्यक्रम, जैविक खेती की परियोजना, एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना, प्रमोशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ़ क्रॉप रेजीडयू, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वालंबन योजना, भूमि संरक्षण अनुभाग योजना का तुलनात्मक प्रगति से अवगत कराया।

उद्यान विभाग की समीक्षा में मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रगति लाने का निर्देश दिया। मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य अमित सिंह को निर्देश दिया ने ग्राम सभा के तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन की अद्यतन प्रगति, मत्स्य बीज वितरण, सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना , निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना , प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड का माहवार लक्ष्य एवं पूर्ति हेतु कैंप लगाने, नवीन मत्स्य जीवी सहकारी समिति का गठन करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर बल दिया। साथ ही बिंद समाज मछुआ समुदाय के अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ दें। बैठक में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ सी वी सचान, जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी इरम, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

त्योहारों से पहले भदोही पुलिस सतर्क बाजारों व संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। आगामी ईद, नवरात्रि और रामनवमी पर्व के मद्देनजर जनपद पुलिस सतर्क हो गई है। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस द्वारा पैदल गश्त व फ्लैग मार्च किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भदोही ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों व वस्तुओं की सघन जांच की।

इस दौरान होटल-ढाबों, बाजारों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने आमजन से संवाद स्थापित कर सभी से त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है।

समयसीमा व गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश, धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी

निर्माण कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सीडीओ बाल गोविंद शुक्ला

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य वकिास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में संचालित सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर, निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाएगी।

समीक्षा के दौरान संस्कृत विद्यालय के निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित कार्यदायी संस्था को कड़ी फटकार लगाई तथा कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त, नत्थईपुर मार्ग के निर्माण कार्य में भी अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य को 15 दिवस के भीतर हर हाल में पूर्ण कराया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्यों को गति प्रदान करें, ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सके।

जिला न्यायाधीश ने कारागार का किया निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के कुशल मार्गदर्शन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही द्वारा जिला कारागार ज्ञानपुर भदोही का निरीक्षण किया गया। जेल में निरूद्ध बन्दियों से उनकी समस्याओं और सुविधाओं के बारे में पूछा गया तथा बन्दियों को निःशुल्क सरकारी अधिवक्ताओं के विषय में जानकारी दी गयी। जेल में पूर्व से संचालित प्रिजन लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महिला बन्दियों से भी मुलाकात की गयी तथा उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया तथा विधिक सलाह दिया गया। जेल निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल भदोही उपस्थित रहे।

पत्नी से विवाद को लेकर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के पास लाश मिली

भदोही। चौरी थाना क्षेत्र के लच्छापुर गांव के सामने अप लाइन रेलवे पटरी के पास एक युवक का मंगलवार की अल सुबह शव पड़ा देख गांव वालों ने शोर मचाना शुरू किया जिस पर लच्छापुर के गेटमैन ने इसकी तत्काल सूचना परसीपुर के स्टेशन मास्टर को दी स्टेशन मास्टर की सूचना पर मौके पर पहुंची चौरी पुलिस शव को कब्जे में लेकर जब तलाशी ली तो मृतक के जेब से एक मोबाइल तथा उसका आधार कार्ड एवं कुछ दूरी पर गैलन में लगभग 2 लीटर पेट्रोल मिला आधार कार्ड पे लिखे नाम पति के आधार पर पुलिस ने घटना की सूचना सूचना मृतक के परिजनों को दी सूचना पर पहुंचे परिजन शव की पहचान वाराणसी जिले के कपसेठी थाना के नेवादा गांव निवासी शैलेंद्र राम के पुत्र सुरेश गौतम 28 वर्ष के रूप में की। परिजनों ने बताया कि बीती देर रात को मृतक घर पर शराब पीकर आया था जिसका उसकी पत्नी जन्नत ने विरोध किया तो दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और मृतक घर से निकलकर पैदल ही चल दिया और सुबह उसकी रेलवे पटरी के पास लाश मिली परिजनों का कहना है कि घटना स्थल मेरे घर से 7 किलोमीटर दूरी पर है जबकि घर के बगल से ही रेल लाइन गुजरती है मृतक रात में यहां कैसे पहुंचा उसके पास पेट्रोल कहां से आया तथा उसके शरीर पर कहीं भी कटने और चोट का कोई निशान नजर नहीं आ रहा है जो मौत को संदिग्ध बना देता है परिजनों का कहना है कि रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था और उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी फिर हाल मृतक दो भाइयों में छोटा था तथा वह एक लड़की और एक लड़के का पिता बताया जाता है घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है थाना प्रभारी चौरी रामसरीख गौतम का कहना है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा।

हाईटेंशन पोल पर चढ़े युवक की पुलिस ने बचाई जान, बड़ा हादसा टला

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। औराई थाना क्षेत्र में पुलिस की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। नशे की हालत में हाईटेंशन बिजली के खंभे पर चढ़े युवक को समय रहते सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मुस्कान' अभियान के तहत डायल 112 पर सूचना मिलते ही पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिजली विभाग से समन्वय कर तत्काल विद्युत आपूर्ति बंद कराई और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सकुशल नीचे उतार लिया। जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान जगदीश यादव निवासी हीरापुर उगापुर, थाना औराई के रूप में हुई है।

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी औराई राजीव सिंह के नेतृत्व में हुई इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है। परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

रईस अहमद उसमानी ने ईद-उल-फितर से पहले सड़क नाली व पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कराने की उठाई मांग

मंत्र भारत संवाददाता

घोसिया, भदोही। आगामी ईद-उल-फितर पर्व को देखते हुए नगर पंचायत घोसिया में जनसमस्याओं को लेकर सामाजिक रूप से सक्रिय रईस अहमद उसमानी ने अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर मार्ग मरम्मत, नालियों की सफाई एवं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है।

रईस अहमद उसमानी ने अपने पत्र में अवगत कराया कि अहले हदीस मस्जिद से लेकर नहरा स्थित ईदगाह तक जाने वाला मुख्य मार्ग काफी जर्जर स्थिति में है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में लोग ईद-उल-फितर की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचते हैं, लेकिन सड़क व नालियों की खराब हालत के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर नालियां पूरी

तरह टूट चुकी हैं और उनके ऊपर रखी पटिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है। विशेष रूप से सत्तार हाशमी, जुम्मन, पप्पू और नसीम के मकानों के पास की स्थिति बेहद खराब है, जहां नाली टूटने, पटिया खुली होने और गंदगी भरी होने से आवागमन में दिक्कत हो रही है। पिछले वर्ष भी ईद के दिन नाली का पानी सड़क पर बहने से नमाजियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।

रईस अहमद उसमानी ने प्रशासन से मांग की है कि ईद-उल-फितर से पूर्व उक्त मार्ग की तत्काल मरम्मत कराई जाए, नालियों की सफाई सुनिश्चित की जाए तथा टूटे हुए पटियों को सही कराया जाए, ताकि नमाज अदा करने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही उन्होंने पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाने, सभी ईदगाहों के मार्गों पर स्वच्छता बनाए रखने तथा नगर में पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने की भी मांग की है, ताकि पर्व के दौरान आमजन को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। स्थानीय लोगों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने की अपील की है, जिससे ईद का त्योहार शांतिपूर्ण और सुविधाजनक वातावरण में संपन्न हो सके।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना गोपीगंज का किया गया आकस्मिक निरीक्षण एवं दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। अभिनव त्यागीपुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा थाना गोपीगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के विभिन्न रजिस्टरों, अभिलेखों के रख-रखाव मिशन शक्ति केंद्र व साइबर हेल्प डेस्क आदि का अवलोकन करते हुए विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। महिला अपराध सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने व लम्बित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। गर्मी के मौसम के दृष्टिगत आगन्तुकों/पीड़ितों के लिए पीने हेतु साफ जल की व्यवस्था/प्रबन्ध करने एवं परिसर की साफ-सफाई हेतु दिये गये विशेष निर्देश। सभी पुलिस अधि0/कर्मचारियों को अच्छा टर्न आउट रखने हेतु निर्देशित किया गया।

एनएसएस शिविर में योग, स्वच्छता, पर्यावरण व स्वास्थ्य जागरूकता का दिया संदेश

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आयोजित सप्त दिवसीय विशेष शिविर के पांचवें दिन मंगलवार को विविध कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मधु विश्वकर्मा द्वारा योग व प्राणायाम से कराई गई, जिसमें स्वयंसेवकों को ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धसेतुबंध आसन के साथ भस्त्रिका, कपालभाति व अनुलोम-विलोम का अभ्यास कराया गया।

इसके बाद डॉ. राममूर्ति व डॉ. श्रीश कुमार उपाध्याय के निर्देशन में शिविर परिसर में साफ-सफाई अभियान चलाया गया। तत्पश्चात डॉ. प्रीति कुमारी, डॉ. मधु विश्वकर्मा, डॉ. श्रीश उपाध्याय एवं डॉ. राममूर्ति की अध्यक्षता में मंदिर प्रांगण में तुलसी, पीपल व गेंदा सहित विभिन्न पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। द्वितीय सत्र में आयोजित संगोष्ठी में रसायन विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सिद्धार्थ बरनवाल ने 'प्लास्टिक मटेरियल का पर्यावरण' विषय पर जानकारी दी। वहीं जंतु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आशुतोष कुमार श्रीवास्तव ने 'महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य व पोषण' पर व्याख्यान दिया।

इस दौरान डॉ. आशुतोष श्रीवास्तव, डॉ. मधु विश्वकर्मा व डॉ. प्रीति कुमारी की अध्यक्षता में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन तथा आयरन व फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण किया गया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. राममूर्ति ने किया। इस अवसर पर पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संतोष कुमार आर्य, डॉ. रमेश कुमार सरोज सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

ऑस्कर 2026 में रेड गाउन में छाईं दीपिका पादुकोण? लुक देख फटी रह गई सबकी आंखें पर सच जान पकड़ लेंगे सिर!

लॉस एंजिल्स के हॉलीवुड डॉल्बी थिएटर में 98वें अकादमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर 2026 का आयोजन किया गया। इस अवॉर्ड शो में दो भारतीय हस्तियां प्रियंका चोपड़ा और ईशा अंबानी के शामिल होने की खबर है। दोनों बतौर प्रेजेंटर शो का हिस्सा बनी है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण की रेड कार्पेट वाली कुछ तस्वीरें जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। ऐसे में कहां एक्ट्रेस के फैंस इस बात से खुश हैं कि, उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस ऑस्कर का हिस्सा बनी है, तो वहीं काफी लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या वाकई में दीपिका ऑस्कर 2026 का हिस्सा बनीं हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में 'ओम शांति ओम' फेम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक खूबसूरत रेड कलर का स्ट्रैपलेस गाउन और प्यारा सा नेकलेस पहने नजर आ रही हैं। एक फोटो में तो वो हॉलीवुड एक्ट्रेस एम्मा स्टोन से बातें करती भी दिख रही हैं। हालांकि, इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। ये फोटो इतनी परफेक्ट है कि, कई लोग इसे देखकर धोखा खा गए और उन्हें लगा की एक्ट्रेस वाकई वहां मौजूद थी, लेकिन ये पिक्चर असली नहीं है, बल्कि एआइ जनरेटेड है।

आपको बता दें कि, दीपिका पादुकोण ने साल 2023 में ऑस्कर अवॉर्ड में शिरकत की थी। तब उन्होंने फिल्में के गाने 'नाटू नाटू' की लाइव परफॉर्मेंस को स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया था। उस समय उनके ब्लैक गाउन वाले लुक ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। मालूम हो कि, ऑस्कर 2026 में दीपिका नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा का जलवा देखने को मिला। एक्ट्रेस बतौर प्रेजेंटर शो में पहुंचीं। उन्होंने एक्टर जेवियर बार्डेम के साथ मिलकर 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म' का अवॉर्ड दिया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जेवियर बार्डेम के उस बयान की हो रही है, जो उन्होंने स्टेज पर दिया।

नव निर्माण के 09 वर्ष पर विकास भवन में होगा मुख्य कार्यक्रम

शासन की योजनाओं की उपलब्धियां होंगी प्रदर्शित, लाभार्थियों को किया जाएगा सम्मानित

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। प्रदेश सरकार के 'नव निर्माण के नव वर्ष' कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद भदोही में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन विकास भवन स्थित पंचायत सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम में शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनपद की प्रमुख उपलब्धियों को प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों, नवाचारों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी दी जाएगी। साथ ही शासन की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगण, जिलास्तरीय अधिकारी, विभिन्न विभागों के कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आमजन की उपस्थिति प्रस्तावित है। कार्यक्रम में जनपद में विगत वर्षों में हुए विकास कार्यों की झलक तथा आगामी विकास योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी।

जिलाधिकारी ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं की जानकारी एवं लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम में समय से उपस्थित रहें तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें। यह कार्यक्रम जनपद में सुशासन, विकास और जनभागीदारी की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगा।

पीड़ित परिवार को एक लाख की आर्थिक सहायता देगी लोजपा (रामविलास), आज पीपर गांव में कार्यक्रम

भदोही। जनपद के ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत पीपर गांव में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) द्वारा अजबएक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व व उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण भारती के निर्देश पर दोपहर एक बजे होने वाले इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान के नेतृत्व में जैसलाल सरोज की धर्मपत्नी को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त करेगा तथा प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी करेगा। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। यह जानकारी लोजपा के उत्तर प्रदेश महासचिव/भदोही प्रभारी कमल तिवारी द्वारा दी गई है।

चार महीने से वेतन नहीं, भिवंडी मनपा के स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश

महिला कर्मचारियों ने जताई आर्थिक तंगी, मनपा मुख्यालय पर किया घेराव

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी मनपा के अंतर्गत 'राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन' में कार्यरत डॉक्टरों, नर्सों और लैब टेक्नीशियन सहित कुल 197 कर्मचारी पिछले चार महीनों से मानदेय न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अपनी लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने मंगलवार को मनपा मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और घेराव किया। जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत भिवंडी क्षेत्र में 192 मुख्य कर्मचारी और 396 आशा वर्कर कार्यरत हैं। इन सभी के मानदेय के लिए प्रतिमाह करीब 70 लाख रुपये के अनुदान की आवश्यकता होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप गाडेकर ने बताया कि दिसंबर माह से सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते कर्मचारियों का वेतन अटका हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत करा दिया गया है। वेतन न मिलने से खासतौर पर महिला कर्मचारियों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। एक महिला कर्मचारी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि पहले से ही कम मानदेय में काम करना पड़ता है, और अब तीन-चार महीनों से वेतन न मिलने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है। कई कर्मचारियों को रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। मंगलवार को मनपा की विशेष महासभा समाप्त होने के बाद पीड़ित महिला कर्मचारियों ने महापौर नारायण चौधरी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। महापौर ने उन्हें बुधवार को प्रत्यक्ष मुलाकात कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। वहीं, नगरसेवक एडवोकेट मयुरेश पाटिल ने भी मनपा आयुक्त अनमोल सागर से मुलाकात कर कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया और लंबित वेतन जल्द जारी करने की मांग की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रस्तावना प्रस्तुत किए बिना ही विशेष सभा में आर्थिक विषयों को मिली मंजूरी

भिवंडी। भिवंडी मनपा की पहली विशेष महासभा में करोड़ों रुपये के आर्थिक खर्चों को मंजूरी देने के प्रस्ताव, प्रशासन द्वारा सदन के सामने औपचारिक रूप से रखे बिना ही चर्चा के बाद मंजूर कर लिए गए। इस कार्यप्रणाली पर कई सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया है।

महापौर नारायण चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस सभा में उपमहापौर तारिक मोमिन, आयुक्त अनमोल सागर, सभी अधिकारी और बड़ी संख्या में नगरसेवक उपस्थित थे।

इस विशेष महासभा में मुख्य रूप से दो बड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई।मानसून पूर्व शहर के छोटे-बड़े नालों और मुख्य सड़कों के किनारे की गटर सफाई के लिए 2,92,99,574 के खर्च को मंजूरी।

480 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरा संग्रहण क्षमता वाले 'ट्रांसफर स्टेशन प्रोजेक्ट' के निर्माण हेतु कुल 19,52,34,572 का प्रस्ताव था। इसमें से नगर पालिका के 30इ हिस्से के रूप में 5,85,70,372 के खर्च को मंजूरी दी गई।नाला सफाई पर हुई चर्चा में मनोज काटेकर, कमलाकर पाटील, फराज बहुद्दीन, एड. वैभव भोईर, सुमित पाटील, नीलेश चौधरी, ऋषिका राका, रोमा आलशी और प्रशांत लाड ने हिस्सा लिया। फराज बहुद्दीन ने सवाल उठाया कि जब पांचों प्रभाग समितियों में गटर और नालों का माप अलग-अलग है, तो प्रस्तावित टेंडर की राशि एक समान कैसे हो सकती है? उन्होंने टूटे हुए चेंबरों की मरम्मत न होने की ओर भी ध्यान दिलाया।

मनोज काटेकर ने कहा कि सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शहर में कहीं भी जलभराव न हो। ऋषिका राका ने काम के ऑडिट और निगरानी की मांग की। आयुक्त अनमोल सागर ने आश्वासन दिया कि सफाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों को साथ लिया जाएगा और श्रमिकों की उपस्थिति के प्रमाणों की जांच की जाएगी। लापरवाही मिलने पर ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। महापौर ने स्पष्ट किया कि देरी से बचने के लिए इस बार दो महीने पहले ही मंजूरी दी जा रही है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत ट्रांसफर स्टेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा हुआ।

सदस्यों ने मांग की कि प्रशासन पहले यह बताए कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार से मिले करोड़ों रुपये कहां खर्च किए गए। प्रशांत लाड ने विरोध जताया कि बिना प्रस्तावना पढ़े चर्चा कैसे शुरू हुई, जिसके बाद उपायुक्त विक्रम दराडे ने प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि ईदगाह (120 टन), म्हाडा कॉलोनी (160 टन) और फेणेपाडा (200 टन) में कचरा एकत्र कर कैप्सूल बनाए जाएंगे और डंपिंग ग्राउंड भेजे जाएंगे।

कमलाकर पाटील ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब डंपिंग ग्राउंड पर कचरा निस्तारण की प्रक्रिया 441 प्रति टन में हो रही है, तो ट्रांसफर स्टेशन पर मशीनरी और प्रोसेसिंग के लिए 670 प्रति टन का दर देना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकारी धन की सरासर बर्बादी है।

आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में एनसीपी ने श्रीकांत चेट्टीपेल्ली को किया निष्कासित

भिवंडी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की भिवंडी शहर इकाई ने अपने पदाधिकारी श्रीकांत शंकर चेट्टीपेल्ली को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी गई। प्रेस नोट के मुताबिक, चेट्टीपेल्ली पर आम जनता के साथ आर्थिक धोखाधड़ी करने के गंभीर आरोप हैं। बताया गया है कि उनके खिलाफ मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया था, जिसके चलते उन्हें करीब तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा। आरोप है कि उन्होंने 'श्री साई तेजा' नाम से एक संस्था बनाकर लोगों को आर्थिक रूप से ठगा। इसके बाद 'भिवंडी मार्कंडेय 'नामक पतसंस्था के जरिए भी कथित रूप से लोगों से धोखाधड़ी की गई, जिसे महज चार महीने के भीतर बंद कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि चेट्टीपेल्ली के इस आचरण से संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा है। साथ ही आशंका जताई गई है कि वह भविष्य में नई योजनाओं के माध्यम से आम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर सकते हैं।एनसीपी ने स्पष्ट किया है कि चेट्टीपेल्ली के किसी भी कृत्य के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। पार्टी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की किसी भी योजना या प्रलोभन से सतर्क रहें। राकांपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण एस. पाटिल द्वारा इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

रमजान में गुलजार हुआ भिवंडी का मार्केट क्षेत्र

बाजारों व मार्केटों में उमड़ रही खरीददारों की बढ़ी भीड़

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। रमजान के शुभारंभ के बाद से ही भिवंडी शहर के लगभग सभी बाजार गुलजार हो गए है।रमजान शुरू होने के बाद से ही मुस्लिम इलाकों और मस्जिदों में रौनक बढ़ गई है। हर तरफ चहल-पहल है।मंदी व महगाई के बावजूद बाजारों में खरीददारों की भीड़ उमड़ रही है।मार्केट में जमकर भीड़ हो रही है।मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों को रंग-बिरंगा सजाया गया है।वहीं दूसरी तरफ पकवानों और दूसरी चीजों के बाजार सज गए हैं।

अल्पसंख्य लोगों की अधिकता के कारण भिवंडी में रमजान व ईद जोरदार तरीके से मनाया जाता है।बाजारों में ईद की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। लोग बड़ी तादाद में रमजान और ईद की तैयारियों के हवाले से बाजारों का रुख कर रहे हैं। बाजारों

में चहल-पहल बढ़ गई है। इस मौके पर जहां कई लोग अपने घरों को सजाने के लिए सजावट का सामान खरीद रहे हैं, वहीं सेहरी और इफ्तार के लिए भी खाने-पीने के सामान के लिए रमजान बाजार सजा दिए गए हैं। शहर के विभिन्न इलाकों कोटरगेट, धामनकरनाका, वंजारपट्टीनाका, दरगाह रोड, मंडई, थाना रोड आदि इलाकों में फल, सब्जियां, नमाज पढ़ने की चटाई, टोपी, लड़कियों का स्कार्फ, रुमाल, इत्र आदि की दुकानें लगाई गई हैं। ईद की खरीददारी भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। बाजारों में खरीददारी के लिए आने वाले शहरियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों की संख्या सर्वाधिक रहती है। ज्यादातर महिलाएं दिनभर रोजा रखने और भीषण गर्मी के कारण दिन में बाजार नहीं जा सकतीं, इसलिए इफ्तार के फौरन बाद बाजारों का रुख कर रही हैं और देर रात तक खरीदारी का यह सिलसिला जारी रहता है।

चटोर गली में बढ़ी भीड़

दुकान चलाने वाले इस्तियाक बताते है कि खाने-पीने की दुकानों, होटलों, ढाबों एवं ठेलों पर खाने के शौकीनों की भीड़ लगी रहती है। यहां की कुछ गलियां ऐसी भी हैं, जहां से लजीज खानों की महक लोगों को अपनी तरफ खींच रही हैं। जहां सेहरी से लेकर इफ्तार तक दूर-दराज के इलाकों से लोग इनका जायका लेने के लिए पहुंच जाते हैं। इन गलियों में सबसे पुराना और अहम नाम चटोर गली है, जो थाना रोड से लगकर है। इस गली में खाने-पीने की दर्जनों दुकानें हैं। जहां सीखकबाब, गुर्दा, कलेजी, पाया, भेजा, गौला और मालपुआ आदि पकवानों चखने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं। इन दुकानों पर खाने के शौकीनों की भीड़ ईशा की नमाज के बाद से सेहरी तक देखी जा सकती है।

पार्किंग की समस्या बढ़ी

इधर स्थानीय निवासी अख्तर काजमी बताते है कि, बाजारों में भीड़ के कारण पार्किंग की समस्या भी बढ़ गई है।बाजारों में इंट्री करने वाले मार्गों को कार ,रिक्शा की इंट्री बंद कर दी जाती है।ताकि मार्केट जाम न हो। खरीदारी के लिए लोगों के लगातार आने से पाकिंग की जगह न होने से लोग सड़कों के किनारे ही अपने वाहन खड़े करने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि यातायात पुलिस की उदासीनता के कारण यातायात की समस्याएं दिनों-दिन बढ़ती जा रही हैं।

प्रदूषण पर बड़ा वार, स्वच्छ हवा मिशन को रफ्तार!

प्रदेश को 'क्लीन एयर' प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से 30 करोड़ डॉलर का फंड

लखनऊ **(एजेंसी)**। विश्वबैंक ने सोमवार को उत्तर प्रदेश को स्वच्छ वायु बदलाव परियोजना के लिए लगभग 30 करोड़ डॉलर का ऋण देने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कर्ज उत्तर प्रदेश सरकार की स्वच्छ वायु योजना को समर्थन देगा। यह राज्य की वायु गुणवत्ता में सुधार और युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एकीकृत समाधान पर केंद्रित है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम (299.66 करोड़ डॉलर) परिवहन, कृषि और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छ वायु बदलाव पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे स्वच्छ वायु के लाभ अन्य राज्यों तक भी पहुंचेंगे।

बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगभग 200 नई वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित किए जाएंगे। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छ वायु प्रबंधन प्राधिकरण की सीईओ और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सचिव बी चंद्रकला और विश्व बैंक की ओर से भारत में कार्यवाहक क्षेत्रीय निदेशक पॉल प्रोसी ने हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य 1, 000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है क्योंकि हमारा मानना है कि आर्थिक वृद्धि, उत्पादकता और पारिस्थितिक संतुलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से, हमारी समृद्धि का मापन केवल जीडीपी से नहीं, बल्कि स्वच्छ आकाश, स्वस्थ और अधिक उत्पादक नागरिकों और एक समृद्ध पर्यावरण से होगा जो हमारे लोगों और हमारे ग्रह को बनाए रखता है।'' पॉल प्रोसी ने कहा कि यह कार्यक्रम परिवहन और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ डॉलर की निजी पूंजी का लाभ उठाएगा। उन्होंने कहा, ''इलेक्ट्रिक बसों और तिपहिया वाहनों में निवेश, उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों और उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करके, यह कार्यक्रम कंपनियों की उत्पादकता और वृद्धि को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ ही राज्य के युवा पुरुषों और महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करेगा।'' कार्यक्रम के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि इससे 39 लाख परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने की सुविधा मिलेगी और 700 से अधिक ईंट-भट्ठे संसाधन-कुशल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित होंगे।

यूपी नगर निगम : योगी सरकार ने 17 नगर निगमों में मनोनीत किए 170 पार्षद

निकायों में नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती प्रदान करते हुए पार्षदों के मनोनयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सोमवार को शासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों सहित नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में नए सदस्यों को नामित किया गया है। शासन से सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के प्रत्येक नगर निगमों में 10-10 पार्षद मनोनीत किये गये हैं।

इस तरह नगर निगमों में कुल 170 पार्षद मनोनीत किये गये हैं। राज्य के नगर निगमों में मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और

गोरखपुर में 10-10 पार्षदों को मनोनीत किया गया है। राज्य में करीब 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं, जिनमें भी सदस्यों को नामित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उप्र इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, ''उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में मनोनीत सभी पार्षदों को हार्दिक बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब राष्ट्रसेवा के संकल्प और समर्पण के साथ अपने-अपने क्षेत्रों के विकास तथा जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।'' उन्होंने कहा, ''हम सभी मिलकर संगठन को नयी ऊर्जा प्रदान करते हुए प्रदेश और राष्ट्र की सेवा के संकल्प को और सशक्त बनाएंगे।'' चौधरी ने कहा, ''भाजपा उत्तर प्रदेश एक परिवार के रूप में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। आप सभी को इस नए दायित्व के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।''

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 'एक्स' पर अपने संदेश में कहा, ''उत्तर प्रदेश के नगर निकायों में मनोनीत समस्त पार्षदों को हार्दिक बधाई तथा सफल व उज्ज्वल कार्यकाल के लिए अनंत शुभकामनाएं!'' मौर्य ने पोस्ट में कहा, ''मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जनसेवा, क्षेत्रीय विकास और संगठन की मजबूती में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वृंदावन दौरे से पहले हाई अलर्ट, चश्मा चोर बंदरों को डराएंगे लंगूर के कटआउट

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से पहले, वृंदावन के कुख्यात बंदरों से निपटने के लिए अधिकारी तेजी से तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने लंगूर के पुतले लगाने और वन विभाग की टीमों को तैनात करने की योजना बनाई है ताकि ये जानवर राष्ट्रपति के चश्मे न छीन सकें। ये असामान्य तैयारियां ऐसे समय में की जा रही हैं जब मुर्मू 19 मार्च को तीन दिवसीय दौरे पर मथुरा आ रही हैं, जिसमें वृंदावन और गोवर्धन भी शामिल हैं। वृंदावन में बंदर चश्मे छीनने और उन्हें भोजन के बदले लौटाने के लिए जाने जाते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि वृंदावन और गोवर्धन के बंदरों से प्रभावित क्षेत्रों में गुलेल और लाठियों से लैस वन विभाग के कर्मियों की टीमें तैनात की जाएंगी। लगभग 30 कर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें से आठ कर्मचारियों को बंदरों की अधिकता वाले क्षेत्रों में और तीन को अपेक्षाकृत कम प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बंदरों को डराने के लिए टीमें लाल और हरी लेजर लाइट भी साथ रखेंगी। एक नए कदम के तहत, अधिकारी प्रमुख स्थानों पर लंगूर की मूर्तियां स्थापित करेंगे। इस कदम का उद्देश्य बंदरों को रोकना है, जो आमतौर पर लंगूरों से दूर रहते हैं। पहले, प्रशिक्षित संचालक वीआईपी दौरों के दौरान जीवित लंगूरों को तैनात करते थे, लेकिन वन्यजीव नियमों के अनुसार अब उनका उपयोग प्रतिबंधित है। अधिकारियों ने इसके बजाय वैकल्पिक उपाय के रूप में मूर्तियों का सहारा लिया है।

प्रशासन की बड़ी कार्रवाई! आंगनवाड़ी सहायिका से भर्ती के लिए 20 हजार की रिश्वत मांगी

सीडीपीओ निलंबित, जांच में ऑडियो क्लिप से मैच हुई आवाज

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के श्रावस्ती जिले में कथित तौर पर आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के बदले 20 हजार रूपये रिश्वत मांगने के आरोप में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। श्रावस्ती के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शाहिद अहमद ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सिरसिया क्षेत्र के सीडीपीओ मुकेश कुमार द्वारा सहायिका की नियुक्ति में रिश्वत लिए जाने की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई जिसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

अहमद ने बताया कि उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की सिफारिश भी की गई है। सीडीओ ने संवाददाताओं को बताया कि प्रियंका आर्य ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति में सिरसिया क्षेत्र के सीडीपीओ 20 हजार रुपये मांग रहे हैं। इस संबंध में फोन पर दोनों के बीच हुई बातचीत की आडियो क्लिप भी पेश की गई।

ईद-उल-फितर पर यूपी पुलिस अलर्ट

मेरठ जिले में सख्त सुरक्षा प्रबंध, 460 ईदगाह 1865 मस्जिदों में नमाज, 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मेरठ में आगामी ईद-उल-फितर पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ परिक्षेत्र में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के अनुसार रेंज के चारों जनपदों में कुल 460 ईदगाह और 1865 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी, जिनकी सुरक्षा के लिए करीब पांच हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे परिक्षेत्र को 23 जोन और 79 सेक्टर में विभाजित किया गया है, जबकि त्वरित कार्रवाई के लिए 66 क्यूआरटी (त्वरित प्रतिक्रिया दल) गठित की गई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा 208 स्थानों को संवेदनशील के रूप में चिन्हित करके वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मेरठ में 158 ईदगाह और 544 मस्जिदों, बुलंदशहर में 150 ईदगाह और 414 मस्जिदों, बागपत में 68 ईदगाह और 451 मस्जिदों तथा हापुड़ में 84 ईदगाह और 456 मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के तहत छह अपर पुलिस अधीक्षक, 22 क्षेत्राधिकारी, 95 निरीक्षक, 805 उपनिरीक्षक, 1100 मुख्य आरक्षी, 1360 आरक्षी, 1090 होमगार्ड/पीआरडी जवान तथा तीन कंपनी पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है।

स्क्वाश के ओलंपिक का हिस्सा बनने के बाद सभी खिलाड़ियो की नजरें लॉस एंजिलिस खेलों पर : अनाहत

मुंबई **(एजेंसी)**। भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह को उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में हर खिलाड़ी का ध्यान मुख्य रूप से लॉस एंजिलिस 2028 खेलों पर होगा क्योंकि इन खेलों के दौरान स्क्वाश ओलंपिक में पदार्पण करेगा। अनाहत ने मंगलवार को यहां कहा कि ओलंपिक में पदक जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है। जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन की टूर्नामेंट से पहले हुई प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अनाहत ने कहा, 'बेशक यह बहुत रोमांचक है। यह पहली बार है जब यह ओलंपिक का हिस्सा बन रहा है और सभी खिलाड़ी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।'

उन्होंने कहा, 'इससे पहले कोई भी खिलाड़ी अधिक से अधिक राष्ट्रमंडल खेलों में खेल सकता था लेकिन अब ओलंपिक भी है और बेशक, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वह ओलंपिक में जाए, खेले और पदक जीते।' अनाहत ने कहा, 'अगले कुछ वर्षों में सभी का यही लक्ष्य रहेगा और दीर्घकाल में मेरे दिमाग में भी यही बात रहेगी कि मैं ओलंपिक तक ट्रेनिंग कर सकूं और संभवतः देश के लिए पदक जीत सकूं।'

जेएसडब्ल्यू इंडियन ओपन पीएसए कॉपर प्रतियोगिता है जो खिलाड़ियों को रैंकिंग अंक हासिल करने का मौका देगा और साथ ही इस साल के आखिर में होने वाले एशियाई खेलों के लिए लय बनाने में भी मदद करेगा। भारत के दूसरे सबसे बेहतर रैंकिंग वाले पुरुष खिलाड़ी रमित टंडन ने कहा कि इस खेल को ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल किए जाने से कारपोरेट जगत भी इसकी ओर आकर्षित हुआ है।

उन्होंने कहा, 'यह (ओलंपिक) दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है इसलिए वहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। इसके अलावा हमारे खेल को जेएसडब्ल्यू और अन्य कारपोरेट घरानों के जुड़ने से भी फायदा हुआ है जो ओलंपिक में शामिल होने के बाद ही संभव हो पाया है।' टंडन ने कहा, 'ओलंपिक में शामिल होने के बाद पूरे स्क्वाश पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है।' टंडन ने कहा कि इंडियन ओपन में खेलने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिलेगी लेकिन स्क्वाश खिलाड़ी पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के हालात पर भी नजर बनाए हुए हैं।

उन्होंने कहा, 'यह स्वदेश में ही हो रहा है इसलिए हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। इसके ठीक बाद मैं लंदन में अगला टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूं। अभी तक उड़ान रद्द नहीं हुई है इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि युद्ध की स्थिति कैसी रहती है।'

टंडन ने कहा, 'तैयारी के लिहाज से विश्व चैंपियनशिप काहिरा में है जो एक प्रभावित इलाका है। हमें पीएसए से ईमेल मिल रहे हैं जिनमें कहा गया है कि वे स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वे तारीखों में थोड़ा-बहुत फेरबदल करने पर भी विचार कर रहे हैं।' अनाहत ने कहा कि वह एक समय में एक ही टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं और 2023 में दो कांस्य पदक जीतने के बाद अब वह एशियाई खेलों में और भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रही हैं।

विश्व कप के हीरो संजू सैमसन हुए भावुक, कहा- 'साबित करना था केरल का लड़का भी जीत सकता है'

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत की टी20 विश्व कप विजेता टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने सोमवार को कहा कि मौजूदा भारतीय टीम निजी उपलब्धियों से अधिक सामूहिक सफलता को प्राथमिकता देती है। उन्होंने इसे ड्रेसिंग रूम में टीम के नेतृत्व समूह द्वारा अपनाई गई एक अहम रणनीति बताया। टी20 विश्व कप के टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे सैमसन ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि टीम के भीतर निजी रिकॉर्ड बनाने के बजाय मैच जीतने पर अधिक जोर दिया जाता है। सैमसन ने कहा, ''अब हर कोई इसी तरह सोच रहा है।

यह हमारे कप्तान और कोच द्वारा ड्रेसिंग रूम में सोच समझकर लिया गया फैसला था। हमारे नेतृत्व समूह की ओर से टीम को लगातार यही संदेश दिया जाता है कि टीम सबसे पहले आनी चाहिए और निजी उपलब्धियां दूसरे नंबर पर।'' उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बीच इस सोच को बार-बार दोहराया गया है। सैमसन ने कहा, ''यह बात अपने आप ही हर एक खिलाड़ी के मन में बैठ गई और इसी तरह हमने हर मैच में प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया।''

सैमसन ने कहा कि क्रिकेट खेलते समय उन्होंने हमेशा खुद के

प्रति ईमानदार रहना पसंद किया है और उनका मानना है कि टीम की सफलता में योगदान देना ही इस खेल का सबसे अहम पहलू है। केरल में जन्मे इस क्रिकेटर ने कहा कि जब से उन्होंने कम उम्र में केरल की ओर से अलग-अलग आयु वर्ग के टूर्नामेंट में खेलना शुरू किया था तभी से वह क्रिकेट को एक टीम खेल के तौर पर देखते आए हैं।

उन्होंने कहा, ''अंडर-13 के दिनों में केरल के लिए खेलने से लेकर आज तक मैं क्रिकेट को हमेशा एक टीम खेल के तौर पर ही देखता हूं। हम जीतने के लिए खेलते हैं। और उस जीत के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, उससे सबसे पहले टीम को ही फायदा होना चाहिए।'' सैमसन ने एक ऐसे क्रिकेटर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी बात की जो केरल से आता है और देश के लिए सर्वोच्च स्तर पर खेलता है। उन्होंने कहा कि कई युवा खिलाड़ी उनके सफर को बहुत करीब से देखते और फॉलो करते हैं।

इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ''बहुत से युवा और अलग-अलग करियर वाले लोग मुझे अपनी जिंदगी जैसा मानते हैं। जब वे मुझे भारतीय टीम में नाकाम होते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इस जगह का कोई लड़का वहां जाकर कुछ हासिल नहीं कर सकता।'' सैमसन ने कहा कि इसी सोच ने उन्हें यह साबित करने के लिए प्रेरित किया कि केरल के खिलाड़ी भी क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर कामयाब हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ''मुझे लगा कि मुझे कुछ साबित करने की जरूरत है। केरल का एक लड़का, त्रिवेंद्रम का एक लड़का भी वहा जाकर क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।

पश्चिम एशिया संकट : निर्यातकों की बढ़ी मुश्किल व्यापार मंडल ने आरबीआई गवर्नर से लगाई राहत की गुहार

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत वाणिज्य मंडल (बीसीसी) ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं शिपिंग मार्गों में व्यवधान से प्रभावित निर्यातकों के लिए सहायक बैंकिंग उपायों की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा को सोमवार को लिखे पत्र में मंडल ने कहा कि पश्चिम एशिया न केवल भारतीय निर्यात का एक प्रमुख गंतव्य है, बल्कि यूरोप व अफ्रीका जाने वाले माल के लिए एक महत्वपूर्ण 'ट्रांस-शिपमेंट' (माल आवाजाही) केंद्र भी है। पत्र में कहा गया '' मौजूदा स्थिति के कारण जहाजों के मार्ग बदल रहे हैं, बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ रही है, माल भाड़ा एवं बीमा लागत बढ़ गई है तथा परिवहन अवधि लंबी हो गई है जिससे निर्यातकों की कार्यशील पूंजी तथा नकदी स्थिति पर दबाव पड़ा है।''

बीसीसी ने आरबीआई से आग्रह किया कि वह बैंकों को कार्यशील पूंजी सीमा बढ़ाकर, तदर्थ ऋण सुविधाएं प्रदान करके और शिपमेंट से पहले व बाद में निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाकर एक सहायक ऋण दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे। इसके अलावा, 'पैकिंग क्रेडिट' के नवीनीकरण में अधिक लचीलापन और निर्यात बिल की देय तिथियों को बढ़ाने की भी मांग की गई है। मंडल ने यह भी अनुरोध किया कि ऋण अदायगी पर स्थगन अवधि को 2026 की पहली और दूसरी तिमाही तक बढ़ाया जाए, ताकि लॉजिस्टिक्स व्यवधान झेल रहे निर्यात क्षेत्रों को राहत मिल सके।

साथ ही, यह भी कहा गया कि शिपिंग में देरी के कारण होने वाली भुगतान देरी पर निर्यातकों को दंडात्मक ब्याज से बचाने और ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) के लाभों की सुरक्षा के लिए नियामकीय राहत दी जाए। बीसीसी ने परिवहन अवधि के नियमों पर मांग की कि उधार अवधि वाले निर्यात बिल के लिए अनुमत समय को '' सामान्य परिवहन अवधि ₹ 25 दिन'' से बढ़ाकर ''₹ 60 दिन '' किया जाए विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के लिए समानता सुनिश्चित करने हेतु।

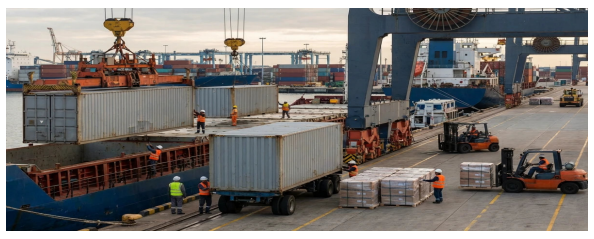

डेवोन कॉनवे की आकर्षक पारी, न्यूजीलैंड ने दूसरे टी20 में दक्षिण अफ्रीका को हराकर श्रृंखला बराबर की

हैमिल्टन **(एजेंसी)**। सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने 60 रन की आकर्षक पारी खेली जबकि तेज गेंदबाज बेन सीयर्स और लॉकी फर्ग्यूसन ने तीन-तीन विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड ने मंगलवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 68 रन से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली।

कॉनवे की 49 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल हैं। उनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया जिसमें जोश क्लर्कसन नाबाद 26 रन बनाकर दूसरे बड़े स्कोरर रहे। इससे न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 175 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 15.3 ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। उसके बल्लेबाजों को पिच की गति और उछाल से सामंजस्य बिठाने में परेशानी हुई। उनकी टाइमिंग सही नहीं थी जिसके कारण उसके सभी बल्लेबाज कैच आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी छह विकेट 40 रन पर गंवाए। जॉर्ज लिंडे की तूफानी पारी के दम पर ही वह 100 रन की संख्या पार कर पाया। लिंडे ने 12 गेंदों में तीन चौकों और इतने ही छक्कों की मदद से 33 रन बनाए।

हाल ही में टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के रिजर्व खिलाड़ी रहे सियर्स ने 14 रन देकर तीन जबकि फर्ग्यूसन ने 16 रन देकर तीन विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान केशव महाराज ने कहा, ''मुझे लगा कि हमने एक समय तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजी में हमारा प्रदर्शन खराब रहा। खेल आगे बढ़ने के साथ विकेट बल्लेबाजी के लिए मुश्किल हो गया था।' तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच शुक्रवार को ऑकलैंड में खेला जाएगा।

टी20 विश्व कप के हीरो सूर्यकुमार बोले- पढ़ाई में फिसड्डी था, अब क्रिकेट में 80 प्रतिशत मिले

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सूर्यकुमार यादव को भले ही पढ़ाई में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उन्होंने आखिरकार 80 प्रतिशत अंक हासिल कर लिए हैं। सूर्यकुमार की अगुवाई में भारत ने हाल में टी20 विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इस जीत का भरपूर आनंद ले रहे सूर्यकुमार का भारतीय कप्तान के रूप में जीत का रिकॉर्ड 80 प्रतिशत है। मुंबई के रहने वाले सूर्यकुमार स्वाभाविक रूप से अपने इन आंकड़ों से बेहद खुश थे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करते समय वह कभी इतने अधिक नंबर लेकर नहीं आए थे।

सूर्यकुमार ने 2024 में टी20 कप्तान का पद संभालने के बाद लगातार सफलता हासिल की। उनकी अगुवाई में भारत ने अभी तक जो 52 मैच खेले हैं उनमें से 42 मैच में उसे जीत मिली है। सूर्यकुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा, ''मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज में मैंने जो प्रतिशत हासिल करने की कोशिश की वह अब मुझे क्रिकेट में मिल रही है।'' उन्होंने कहा, ''वहां (स्कूल या कॉलेज में) मैं कभी 50-60 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। लेकिन यह (जीत की दर 80 प्रतिशत) सुनकर वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे आंकड़ों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करता हूं लेकिन किसी को भी किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं होता और मुझे भी जीतना पसंद है।''

सूर्यकुमार के पिता अशोक कुमार यादव भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। लेकिन सूर्यकुमार का कभी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा और उनके परिवार ने क्रिकेट में उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा, ''मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाई में अच्छा करने के लिए बहुत प्रेरित किया लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि इस लड़के को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह लड़का उनके हाथ नहीं आएगा।'' सूर्यकुमार ने कहा, ''लेकिन उन्होंने खेल में मेरा हमेशा समर्थन किया क्योंकि उन्होंने पाया कि इसमें मुझे पूरा आनंद आ रहा है और मुझे खेलना पसंद है। इसलिए उन्होंने कहा, 'ठीक है, जाओ खेलो। अगर कुछ हासिल नहीं होता है तो फिर ख्याल रखने के लिए हम तो हैं ही।'' हमेशा मुस्कुराते रहने वाले इस दिग्गज बल्लेबाज ने हालांकि ऐसी नौबत नहीं आने दी जिससे कि उन्हें 'प्लान बी' का सहारा लेना पड़े।

'सरके चुनर' के बोल सुन दुखी हुए अरमान मलिक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सिंगर का रिएक्शन

साउथ की फिल्म 'केडीः द डेविल' का नया गाना 'सरके चुनर तेरी सरके' इन दिनों सुर्खियों में तो है, लेकिन यह अपनी अच्छाई की वजह से नहीं बल्कि विवादों के कारण। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माए गए इस गाने के बोल और डांस स्टेप्स को लेकर लोग सोशल मीडिया पर काफी भड़के हुए हैं। अब इस विवाद में मशहूर सिंगर अरमान मलिक भी कूद पड़े हैं। अरमान ने इस गाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और इसे भारतीय संगीत के लिए एक बुरा दौर बताया है। अरमान की इस बेबाकी की अब हर तरफ चर्चा हो रही है।

अरमान मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस गाने की एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि जब यह गाना उनकी टाइमलाइन पर आया, तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने इसे दोबारा सुना ताकि वो पक्का कर सकें कि जो उन्होंने सुना है, क्या वाकई किसी फिल्म के गाने में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो सकता है। अरमान ने बड़े दुखी मन से कहा कि यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि आज के दौर में गाने लिखने का लेवल इतना नीचे गिर गया है। उनके इस पोस्ट के बाद लोगों ने उनकी ईमानदारी की जमकर तारीफ की है।

अरमान के इस पोस्ट पर फैंस के भी खूब कमेंट्स आ रहे हैं। एक फैन ने जब उनसे कहा कि 'शुक्र है आपने अपने करियर में कभी ऐसा गाना नहीं गाया और उम्मीद है आगे भी नहीं गाएंगे, ' तो अरमान ने फौरन जवाब दिया 'भाई, कभी भी नहीं' अरमान के भाई अमाल मलिक ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि वे ऐसे गानों का हिस्सा नहीं बनेंगे जो महिलाओं का अपमान करते हों। फैंस कह रहे हैं कि दोनों भाइयों ने संगीत की मर्यादा को बचाए रखा है और उन्हें अपनी पसंद पर गर्व है।

दूसरी तरफ, लोग इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन जन्या, लेखक रकीब आलम और सिंगर मंगली को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि पैसे और सस्ते व्यूज के लिए महिलाओं को इस तरह ऑब्जेक्टिफाई करना शर्मनाक है। जहां तक फिल्म की बात है, तो 'केडीः द डेविल' एक बड़े बजट की कन्नड़ फिल्म है जो 1970 के दशक के अंडरवर्ल्ड पर आधारित है। फिल्म में ध्रुव सरजा और शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े सितारे भी हैं, लेकिन फिलहाल इस गाने की अश्लीलता ने फिल्म की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

एसी/ई/एसआर/753/एमओएच/दिनांक 12.03.2026

अभिरुचि अभिव्यक्ति हेतु विज्ञापन

विषयः ई वार्ड के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में 'डी' श्रेणी के बहुउद्देशीय कर्मियों के रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने के संबंध में।

ई वार्ड के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के औषधालयों, कार्यालयों तथा शवदाह गृहों में 'डी' श्रेणी के रिक्त पदों को अनुबंध के आधार पर भरने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं (बचत समूहों को छोड़कर) के माध्यम से बहुउद्देशीय कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। इसके लिए केवल वही संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें बृहन्मुंबई महानगरपालिका के औषधालयों, कार्यालयों तथा शवदाह गृहों में अनुबंध के आधार पर बहुउद्देशीय कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

इच्छुक संस्थाओं में भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पंजीकृत मजदूर सहकारी संस्थाएं, सेवा सहकारी संस्थाएं, बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थाएं तथा गैर-सरकारी संगठन आदि आवेदन कर सकते हैं। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य अपने सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराना होना चाहिए।
ऐसी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, ताकि उनकी पात्रता सूची तैयार की जा सके और बाद में लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयन किया जा सके।

आवेदन प्रपत्र 18.03.2026 से 24.03.2026 तक सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच ई वार्ड के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी, आवेदन प्रपत्र तथा शपथपत्र प्रपत्र प्राप्त करने के लिए इच्छुक संस्थाएं जी/दक्षिण वार्ड के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। संस्था द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24.03.2026, समय शाम 5:00 बजे तक है।
निर्धारित कार्यालय समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी
ई वार्ड

पीआरओ/3313/विज्ञा./2025-26

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

काबुल नरसंहार पर राशिद खान का गुस्सा! पाकिस्तान पर लगाया 'युद्ध अपराध' का आरोप, बोले- 'यह घिनौनी हरकत है'

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर और पूर्व कप्तान राशिद खान ने काबुल के एक अस्पताल पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। हमले में मरने वालों की संख्या 400 तक पहुँचने के बाद राशिद ने इसे 'युद्ध अपराध' करार देते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। राशिद खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक बेहद भावुक और कड़ा संदेश साझा किया। उन्होंने लिखाः 'आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना एक युद्ध अपराध है। रमज़ान के पवित्र महीने में इंसानी जानों की ऐसी घोर अनदेखी बेहद घिनौनी और चिंताजनक है। इससे केवल नफरत और फूट ही बढ़ेगी।'

उन्होंने यह भी कहा कि यह ताज़ा हरकत सिर्फ़ फूट और नफ़रत को ही बढ़ावा देगी। राशिद ने मानवाधिकार संगठनों से अपील की कि वे आगे आएं और इस ताज़ा ज़ुल्म की जाँच करें। राशिद खान ने एक्स पर लिखा, 'काबुल में

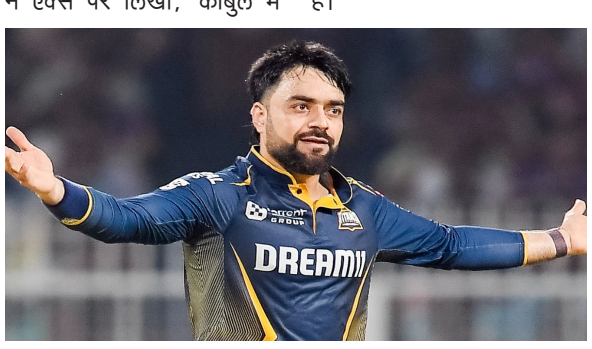

पाकिस्तानी हवाई हमलों के चलते आम नागरिकों के मारे जाने की ताज़ा खबरों से मैं बहुत दुखी हूँ। आम नागरिकों के घरों, शिक्षण संस्थानों या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना–चाहे जानबूझकर हो या गलती से–एक युद्ध अपराध है। इंसानी जान की सरासर अनदेखी, खासकर रमज़ान के पवित्र महीने में, बेहद घिनौनी और गहरी चिंता का विषय है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इससे सिर्फ़ फूट और नफ़रत ही बढ़ेगी। मैं संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवाधिकार एजेंसियों से अपील करता हूँ कि वे इस ताज़ा ज़ुल्म की पूरी जाँच करें और दोषियों को सज़ा दिलाएं। इस मुश्किल घड़ी में मैं अपने अफगानी लोगों के साथ खड़ा हूँ। हम इस दुख से उबरेंगे, और एक राष्ट्र के तौर पर फिर से उठ खड़े होंगे। हम हमेशा ऐसा ही करते आए हैं।'

काबुल के एक अस्पताल पर कथित हवाई हमला तब हुआ, जब अफ़ग़ान अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान की सेनाओं के बीच सीमा पर गोलीबारी हुई। सीमा पार हुई इन झड़पों में दोनों देशों के बीच पिछले कई सालों में सबसे भीषण लड़ाई देखने को मिली है। दोनों देशों के बीच लड़ाई इस साल फरवरी में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत सीमा पार से हुए हमलों से हुई, जिसके जवाब में दोनों तरफ से जवाबी हमले किए गए। पाकिस्तान ने इस स्थिति को 'खुला युद्ध' बताया, जबकि अफ़ग़ान अधिकारियों ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा करना सभी नागरिकों की ज़िम्मेदारी है।

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

मुख्य कार्यालय, स्व. इंदीरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (पश्चिम) ता.जि.ठाणे - ४०११०१
// फेर निविदा सुचना //

जा.क्र. मनपा/पंअण्डपार्क/१८१/२०२५-२६ दि.१७/०३/२०२६

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका मौजे नवघर स.क्र. ४५२/३, व ३९२/१ (आरक्षण क्र.३०१) या जागेत विकासकाने बांधलेले व हस्तांतर केलेले पे ॲण्ड पार्क (वाहनतळ) ठेका पध्दतीने चालविणे करीता एजन्सी / संस्था यांचेकडून मोहोरबंद दर E-Tendering पध्दतीने मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाचे कोरे निविदा फॉर्म दि.१८/०३/२०२६ ते दि. १३/०४/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या ETendering संकेतस्थळ https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील. निविदाधारकाने निविदा फॉर्म फी व इसारा रक्कम ऑन लाईन भरणा करावी, अन्यथा निविदा ग्राहय समजण्यात येणार नाही. सदर कामी मागविलेल्या मोहरबंद फेर निविदा दि. १३/०४/२०२६ रोजी दुपारी-०१.०० वाजेपर्यंत वरील संकेतस्थळावर स्विकारण्यात येतील व शक्यतोवर दि.१६/०४/२०२६ दुपारी-०४.०० वाजता उपस्थित ठेकेदार व त्यांचे प्रतिनिधी समक्ष उघडण्यात येतील. संबंधित एजन्सी/संस्थेने मिरा भाईंदर महापालिकेच्या ई-टेंडर विभागाकडे संपर्क साधून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्रकारची ऑन लाईन निविदा स्विकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचा अंतिम अधिकार मा. आयुक्त सो. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी राखून ठेवला आहे.

अ.क्र.	कामाचे नाव	इसारा रक्कम	ठेका रक्कम	कराराची मुदत
१	मौजे नवघर स.क्र. ४५२/३, व ३९२/१ (आरक्षण क्र.३०१) या जागेत विकासकाने बांधलेले व हस्तांतर केलेले पे ॲण्ड पार्क (वाहनतळ) ठेका पध्दतीने चालविणे	रू.६०,३८७/-	रू.६०,३८,७००/-	२ वर्षे

जा.क्र. मनपा/म्हावज/E-८६२८०८०/२०२५-२६ दि. १७/०३/२०२६
(मा. आयुक्त यांचे मान्यतेने)
ठिकाण : भाईंदर
दिनांक : 17/3/2026

(प्रणाली घोंगे)
उप. आयुक्त (पे ॲण्ड पार्क)
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

देश में राष्ट्र प्रथम का भाव एवं पंच परिवर्तन का स्वभाव बनेः प्रांत संघचालक सरदार स्वर्ण सिंह

नई दिल्ली। लखनऊ : अवध प्रान्त के प्रांत संघचालक सरदार स्वर्ण सिंह एवं सह प्रांत कार्यवाह संजय सिंह ने समालखा हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मीडिया सेंटर विश्व संवाद केन्द्र जियामऊ लखनऊ में आयोजित प्रेसवार्ता में बैठक में संगठन कार्य के विस्तार, राष्ट्र हित में समाज की सज्जनशक्ति की सक्रिय भागीदारी एवं सामाजिक समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रांत संघचालक सरदार स्वर्ण सिंह जी ने बताया कि बैठक में संत शिरोमणि सद्?गुरु श्री रविदास जी के 650 वें प्राकट्य वर्ष के अवसर पर सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जब विभिन्न विभाजनकारी शक्तियां समाज को वर्ग और जाति के आधार पर विभाजित करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं तब संत रविदास जी के जीवन संदेश के मर्म को समझते हुए समाज की एकात्मकता के लिए कार्य करने का संकल्प लेने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि समाज में महापुरुषों के श्रेष्ठ कार्यों को जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर स्वीकार करना चाहिए। देश में राष्ट्र प्रथम का भाव एवं पंच परिवर्तन का स्वभाव बने, इसी भाव भावना से संघ के स्वयंसेवकों ने सिख परम्परा के नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी के बलिदान के 350वें वर्ष के अवसर पर देशभर में 2000 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। अवध प्रांत में भी 24 स्थानों पर 24

कार्यक्रम सम्पन्न हुए, जिसमें 10000 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया।

सह प्रान्त कार्यवाह संजय सिंह जी ने बताया कि विगत विजयादशमी से देश भर में अधिक संख्या में सम्पन्न उत्सवों के साथ ही शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। इन विविध कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं की व्यापक योजना एवं परिश्रम के अनुसार सर्वत्र सफलता मिली। समाज बंधुओं ने उन्हें सहर्ष तथा हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए सहयोग एवं समर्थन दिया। संघ के निमंत्रण पर समाज के विभिन्न वर्गों-श्रेणियों के बंधु भगिनी उत्साह से सहभागी होकर कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से सम्पन्न करने में अपार योगदान दिए। मंडल बस्ती स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के कारण संगठन की दृष्टि से समाज की छोटी इकाई तक पहुँचने में बड़ी सफलता मिली है। गृह सम्पर्क के कारण संघ को, संघ के विचारों को घर घर तक पहुँचाना सम्भव हो रहा है । सद्भाव बैठकों और नागरिक गोष्ठी से समाज में सकारात्मक चिंतन एवं कर्तव्य बोध का निर्माण हो रहा है ।समाज संघ की 100 वर्ष की यात्रा को समझते हुए राष्ट्र जीवन में संघ से अधिकाधिक अपेक्षा भी कर रहा है। पंच परिवर्तन के विषयों का सर्वत्र स्वागत है। संघ के बारे में जानने की तथा सामाजिक कार्यों के बारे में उत्सुकता बढ़ रही है।

अवध प्रांत में संगठनात्मक कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रान्त के कुल 2888 मंडल, बस्ती में से 2860 में शाखा है, 2728 मंडल, बस्ती में हिन्दू सम्मेलनों का आयोजन किया गया। कुल 18993 गाँवों में से 15864 गाँवों में घर घर सम्पर्क किया गया । सामाजिक सद्भाव की 294 बैठकें एवं 124 केन्द्रों पर प्रमुख जन गोष्ठियों का आयोजन किया गया। शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम आगामी विजयदशमी तक सम्पन्न होंगे, आगे युवा पीढ़ी में राष्ट्रबोध, संगठन स्वभाव एवं समाज परिवर्तन के प्रयत्न की वृद्धि को ध्यान में रखकर युवकों में कार्य बढ़ाने की योजना है, कार्य विस्तार की दृष्टि से अधिकतम स्थानों पर अधिकतम कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाते हुए अधिकतम शाखाएं खड़ी करने की योजना है। संघ का काम निरंतर चलने वाला काम है, शताब्दी वर्ष वास्तव में संघ की 100 वर्ष की यात्रा का अनुवर्तन ही है। शताब्दी वर्ष में समाज की बहुत बड़ी सज्जन शक्ति, सुप्त शक्ति एवं उत्सुक शक्ति का अनुवर्तन करते हुए 'राष्ट्र प्रथम का भाव' एवं 'पंच परिवर्तन का स्वभाव' उत्तरोत्तर बढ़ता रहे इस हेतु आवाहन किया गया।

अन्त में आए हुए सभी पत्रकार बन्धुओं का आभार व्यक्त किया गया और होली की शुभकामनाएँ प्रेषित की गई। होली मिलन के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रचार प्रमुख सुभाष जी भी उपस्थित रहे।

आरोग्य भारती एवं विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन - डॉ जी एस तोमर

प्रयागराज। सुदर्शन आयुर्वेद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कतवारूपुर शाखा, हनुमानगंज में आरोग्य भारती एवं विश्व आयुर्वेद मिशन द्वारा प्रवेक कल्प के सौजन्य से 18 मार्च को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है । जिसमें विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष एवं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ जी एस तोमर, डॉ सुभाष राय एवं डॉ अवनीश पाण्डेय रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सा परामर्श प्रदान करेंगे तथा फिजियोथेरापिस्ट जी एस मिश्रा गठिया, सर्वाइकल एवं लम्बर स्पोन्डिलाइटिस के रोगियों को फिजियोथेरापी का प्रशिक्षण देंगे । इस शिविर में प्रवेक कल्प के सौजन्य से निः शुल्क बीएमडी (हड्डियों की जाँच) एवं ब्लड शुगर की जाँच की जाएगी । शिविर के संयोजक राजेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सुदर्शन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कतवारू शाखा में इस प्रकार के निःशुल्क शिविर प्रति माह आयोजन करने की योजना है । सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वह समय से पहुँचकर शिविर का लाभ उठाएँ ।

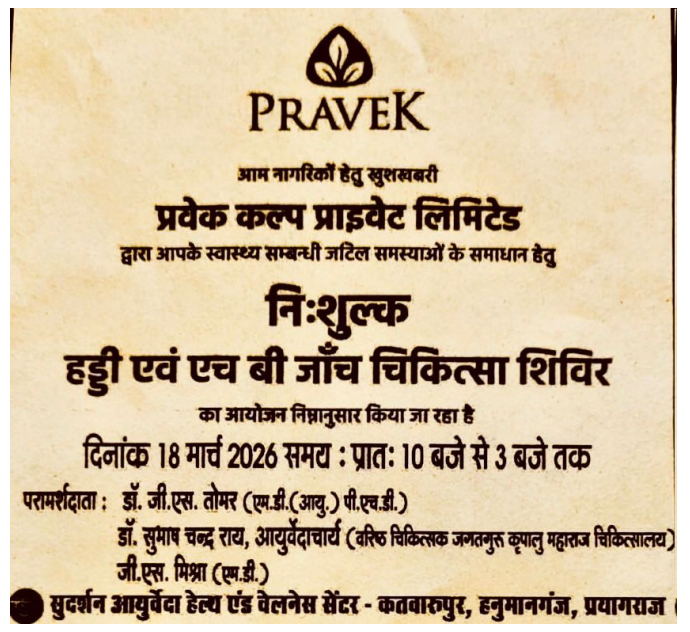

रेल मंत्री बोलेः तेज़, सुरक्षित और आधुनिक बन रही है भारतीय रेल

नई दिल्ली। केंद्रीय रेल मंत्री ने संसद में कहा कि तेज़, सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक परिवहन प्रणाली के रूप में तेजी से बदल रही है तथा यह आम आदमी और मध्यम वर्ग की सवारी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब और आम नागरिकों को सस्ती और बेहतर रेल यात्रा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेल के लिए लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया गया है, जिससे रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 1.37 लाख किलोमीटर रेल नेटवर्क और 25 हजार से अधिक ट्रेनें प्रतिदिन संचालित हो रही हैं, जो लोगों और माल को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने बताया कि रेलवे में सुरक्षा और

तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेशी कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को तेजी से लागू किया जा रहा है और इसके चलते रेल दुर्घटनाओं में करीब 90 प्रतिशत तक कमी आई है। साथ ही ट्रैक निर्माण, विद्युतीकरण और आधुनिक एलएचबी कोचों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों को किफायती यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर साल लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, जिससे प्रत्येक यात्री टिकट पर औसतन 45 प्रतिशत तक खर्च सरकार वहन करती है। उन्होंने बताया कि रेलवे में लगभग 70 प्रतिशत कोच सामान्य और स्लीपर श्रेणी के हैं, जिससे आम यात्रियों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें और 60 अमृत भारत ट्रेन सेवाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा मुंबई के लिए 238 नई उपनगरीय ट्रेनें तथा देश में 200 नई इंटरसिटी ट्रेनें शुरू करने की योजना है। रेल मंत्री ने बताया कि पिछले दस वर्षों में रेलवे में करीब 5 लाख नौकरियां दी गई हैं और स्टेशन पुनर्विकास के तहत देशभर के 1300 से अधिक स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल का तेजी से हो रहा यह परिवर्तन देश की अर्थव्यवस्था और यात्री सुविधाओं को नई दिशा देगा।

शिवराज का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले- कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही, गरीबी नहीं हटाई

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ग्रामीण रोजगार योजनाओं के नाम बदलने को लेकर विपक्ष पर छोटी राजनीति करने और मोदी सरकार के तहत गरीबी में जी रहे लोगों को मिले वास्तविक लाभों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मूल रूप से एनआरईजीए) में किए गए बदलावों को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि यह योजना महात्मा गांधी के नाम के बिना शुरू की गई थी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए बाद में उनका नाम जोड़ा।उन्होंने बताया कि कई योजनाओं का नाम गांधी परिवार के पूर्व प्रधानमंत्रियों - जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी - के नाम पर रखा गया है।

चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

एक साथ बदले जाएंगे 13 जिलों के एसपी; कुल 19 अफसरों का तबादला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का एलान होने के बाद से बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हो चुका है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को भी 19 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। तबादला किए गए अधिकारियों में उत्तर, दक्षिण बंगाल के एडीजी भी शामिल हैं। इससे पहले राज्य के मुख्य सचिव का भी तबादला किया जा चुका है।

कई जिलों में प्रशासनिक फेरबदल

आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को दक्षिण बंगाल का नया एडीजी नियुक्त किया गया है। वहीं के जयरामन को उत्तर बंगाल के एडीजी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों 1997 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। आसनसोल-दुर्गापुर, हावड़ा, बराकपोर और चंदननगर जिलों में भी नए कमिश्नर ऑफ पुलिस की नियुक्ति की गई है। 13 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी ताजा फेरबदल में बदले गए हैं।

मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी पद से हटाया गया

विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद निर्वाचन आयोग ने बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पद से हटा दिया था। आयोग ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों अधिकारी किसी भी चुनाव संबंधी काम में शामिल नहीं हो सकेंगे। नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुश्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 1997 बैच की अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य का नया गृह सचिव बनाया गया है।

आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग करता है प्रशासनिक फेरबदल

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग को प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का अधिकार मिल जाता है। निर्वाचन आयोग पहले भी चुनाव के दौरान राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में बदलाव करता रहा है। गृह सचिव स्तर पर भी पहले परिवर्तन हुए हैं, हालांकि मुख्य सचिव स्तर पर बदलाव सामान्य नहीं रहा है।

बंगाल में दो चरणों में होंगे चुनाव

294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को नतीजे घोषित होंगे।

ब्रुसेल्स में एस जयशंकर की दो टूक, बोले-

पश्चिम एशिया संकट का हल सिर्फ संवाद और कूटनीति

बेल्जियम **(एजेंसी)**। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कल्लास के निमंत्रण पर ब्रुसेल्स गए थे। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि नेताओं ने संकट को समाप्त करने के लिए संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारे विदेश मंत्री ब्रुसेल्स गए थे। उन्हें यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने यूरोपीय संघ की विदेश परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। बैठक में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों पर चर्चा के अलावा, उन्होंने और यूरोपीय संघ के अन्य मंत्रियों, विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक चुनौतियों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थिति, और ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर चर्चा की। मंत्रियों ने इस विशेष संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

जयशंकर दो दिवसीय दौरे पर ब्रुसेल्स गए थे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ब्रसेल्स का मेरा दौरा फलदायी रहा। मैंने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद से मुलाकात की, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार उपाध्यक्ष काजा कल्लास से बातचीत की। इसके अलावा, मैंने यूरोपीय संघ के समकक्षों से भी मुलाकात की और कई अन्य लोगों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय चर्चाएं कीं। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने दस प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने इन बिंदुओं पर चर्चा कीः मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देना भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका

बीएलए के समन्वित हमलों में 25 से ज्यादा सैनिक ढेर

इस्लामाबाद **(एजेंसी)**। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के मीडिया विंग हक्कल द्वारा जारी एक बयान में, समूह ने 14 से 16 मार्च के बीच क्षेत्र में सिलसिलेवार समन्वित हमलों का दावा किया है। बीएलए के अनुसार, सशस्त्र समूह ने तीन दिनों के दौरान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और काफिलों को निशाना बनाते हुए कई अभियान चलाए। पहला हमला कथित तौर पर 14 मार्च को खारान जिले के गरुक इलाके में हुआ। बीएलए ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने रॉकेट और अन्य भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया। समूह के अनुसार, हमले के दौरान कम से कम छह सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हुए, जिससे 14 सैनिक शहीद हो गए, जबकि दस से

अधिक घायल हो गए।

समूह ने यह भी बताया कि एक दिन पहले, उसके लड़ाकों ने उसी क्षेत्र में एक सैन्य चौकी पर खाद्य सामग्री ले जा रहे एक ट्रक को रोका था। वाहन को बाद में आग लगा दी गई, जबकि चालकों को कथित तौर पर बिना किसी नुकसान के छोड़ दिया गया, जिसे बीएलए ने अपनी परिचालन नीति के अनुरूप बताया। 15 मार्च को एक और हमले की सूचना मिली, जब बीएलए लड़ाकों ने कथित तौर पर तुरबत हवाई अड्डे पर एक सैन्य अड्डे और जेट ईंधन भंडारण सुविधा को निशाना बनाया।

बयान के अनुसार, हमले में ग्रेनेड लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया, जिससे घटनास्थल पर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हालांकि, कथित नुकसान की स्वतंत्र पुष्टि तुरंत उपलब्ध नहीं थी। उसी दिन, समूह ने दावा किया कि उसकी एक शहरी गुरिल्ला इकाई ने ग्वादर जिले के जिवानी के पनवान क्षेत्र में तटरक्षक चौकी पर एक सुनियोजित हमला किया। बीएलए ने आरोप लगाया कि हमले से पहले उसके लड़ाकों ने अपना वेश बदला था, जिसके परिणामस्वरूप नायक सलीम, सिपाही अदनान राव और सिपाही अजीम सहित तीन तटरक्षक कर्मियों की मौत हो गई। समूह ने चौकी से हथियार और गोला-बारूद जब्त करने का भी दावा किया। 16 मार्च को एक अलग अभियान में, बीएलए ने कहा कि उसने डुक्की जिले के बख्तियार लोनी इलाके में पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाकर एक रिमोट-कंट्रोल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस में विस्फोट किया। खबरों के मुताबिक, विस्फोट में एक सैन्य वाहन नष्ट हो गया और दस सैनिक मारे गए।

सोशल मीडिया पर जंग नहीं जीती जाती

बड़बोले ट्रंप और उनकी सेना को कीबोर्ड वॉरियर बताते हुए ईरान ने गजब धोया

वाशिंगटन। ईरान के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बड़बोलेपन पर पलटवार किया है। इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी ने कहा कि युद्ध का फैसला बैटल ग्राउंड में होता है सोशल मीडिया पर नहीं। उन्होंने अमेरिकी अभियान के नाम एपिक फ्यूरी का मज़ाक उड़ाते हुए कहा कि इसे एपिक फियर कहना ज़्यादा सही होगा। ये टिप्पणियां ईरान के खातम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय और सशस्त्र बलों के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी ने कीं, जिन्होंने मौजूदा तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के दृष्टिकोण की आलोचना की।

उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक जीत जमीनी अभियानों से मिलती है, न कि ऑनलाइन बयानबाजी से और किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने के लिए ईरान की तत्परता पर जोर दिया। ये टिप्पणियां संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच आई हैं, जहां ईरान कथित तौर पर एक मजबूत जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिसे कुछ अधिकारियों द्वारा अंतिम चरण बताया गया है। बढ़ती बयानबाजी ने वैश्विक चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों पक्षों के बयान क्षेत्र में पहले से ही नाजुक स्थिति को और भी गंभीर बना रहे हैं। गौरतलब है कि दो हफ्ते से ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं। ईरान को हरा दिया। इसके बाद भी दुश्मन के समंदर में पांव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। दो दिनों से ट्रंप अपील कर रहे हैं। अभी तक किसी देश ने अपने युद्धपोत भेजने का वादा नहीं किया। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह इस महीने के अंत में चीन की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा को स्थगित कर सकते हैं क्योंकि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में मदद करने और ईरान युद्ध के कारण आसमान छू रही तेल की कीमतों को कम करने के लिए बीजिंग पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं।

एक तस्वीर से दो निशाने! इजरायल ने नेतन्याहू की तस्वीर जारी कर ईरान और अफवाहों को एक साथ दिया जवाब

यरुशलम **(एजेंसी)**। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें कथित तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर इजरायल-ईरान संघर्ष में एक तीव्र वृद्धि का संकेत देती है। तस्वीर में लिखा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरानी शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को खत्म करने का आदेश दे रहे हैं। तस्वीर में उन्हें एक कमांडिंग सीट पर दिखाया गया है, जबकि ईरान के साथ संघर्ष जारी है और दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यह पोस्ट ऑनलाइन अटकलों के बीच आई है, जिनमें अपुष्ट दावे और षड्यंत्र सिद्धांत शामिल हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नेतन्याहू ईरानी हमलों में मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। इजरायली और स्वतंत्र तथ्य जांचकर्ताओं ने बार-बार इन दावों को खारिज करते हुए पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री जीवित हैं और अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने इस तस्वीर को इस बात के सबूत के तौर पर पेश किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के नेतृत्व के खिलाफ लक्षित हमलों के फैसलों की सीधी निगरानी कर रहे हैं। ये हमले ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लगातार हवाई और मिसाइल हमलों से चिह्नित इजरायल और अमेरिका के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर किए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच तनाव असामान्य रूप से बढ़ गया है। इजरायली हमलों में अली लारीजानी समेत कई वरिष्ठ ईरानी नेताओं के मारे जाने की खबरें हैं, जबकि तेहरान ने पूरे क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की लहरों से जवाबी कार्रवाई की है।

इसराइल-ईरान युद्ध : इजरायल का बड़ा दावा बाजिस फोर्स के चीफ सुलेमानी की मौत

तेल अवीव **(एजेंसी)**। रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज़ ने मंगलवार को बताया कि ईरान की सुरक्षा रणनीति का नेतृत्व करने वाले और संघर्ष के दौरान तेहरान का चेहरा रहे अली लारीजानी इजरायली हमलों में मारे गए। इस घटनाक्रम से ईरानी नेतृत्व और भी कमजोर हो गया है, जिसने हमलों के पहले ही दिन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को खो दिया था। उनके उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनेई भी कोमा में बताए जा रहे हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। एक अन्य शीर्ष कमांडर, गुलामरेज़ा सुलेमानी, सोमवार रात इजरायली हवाई हमलों में मारे गए थे। ईरान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इज़राइल की घोषणा उसी समय हुई जब लारीजानी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक हस्तलिखित संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 4 मार्च को अमेरिकी पनडुब्बी हमले में मारे गए ईरानी नौसैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

मोजतबा की हालत के बारे में कोई खबर न होने के कारण, 67 वर्षीय लारीजानी ईरान में वस्तुतः दूसरे नंबर के नेता थे और संक्रमणकालीन परिषद के साथ मिलकर इस संकटग्रस्त देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यह घटनाक्रम लारीजानी द्वारा ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के नेटवर्क के सदस्यों द्वारा ईरान को फंसाने के लिए 9/11 जैसी घटना की 'साजिश' की चेतावनी देने के एक दिन बाद आया है।

लारीजानी, जिन्होंने पहले अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का नेतृत्व किया था और खामेनेई के करीबी सहयोगी थे, को आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में एक रैली के दौरान देखा गया था। उनके साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन भी मौजूद थे। उसी दिन बाद में अमेरिका ने लारीजानी समेत वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 मिलियन डॉलर (92 करोड़ रुपये) तक का इनाम देने की घोषणा की। लारीजानी, अयातुल्ला खामेनेई के बाद मारे जाने वाले सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। खामेनेई की हत्या 28 फरवरी को संघर्ष के पहले ही दिन कर दी गई थी। ईरानी शासन के शांत और व्यावहारिक चेहरे के रूप में गिने जाने वाले लारीजानी ने संघर्ष शुरू होने के बाद अमेरिका और इज़राइल को 'एक अविस्मरणीय सबक' की चेतावनी दी थी।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)